● वर्ष-4
● अंक-89
रायपुर, शुक्रवार
22 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» सर्दियों में सांस के रोगी रहें सचेत....

भारत वैश्विक विकास के पक्ष में-मोदी

जॉर्जटाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुयाना में संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम व्यवसाय पर संसाधनों का उपयोग करते हैं। संसाधनों को हथियाने की भावना से हमेशा दूर रहते हैं। आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है।

पीएम ने कहा कि आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम प्रथम प्रतिक्रियादाता बनकर वहां पहुंचें। कोविड-19 के दौरान जब हर देश खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब भारत ने 150 से अधिक देशों के साथ दवाइयां और वैक्सीन साझा कीं।

उन्होंने कहा कि भारत और गुयाना का रिश्ता बहुत गहरा है। यह मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। करीब 180 साल पहले एक भारतीय गुयाना की धरती पर आया था और उसके बाद से सुख और दुख दोनों में भारत और गुयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है।

पिछले 200-250 वर्षों में भारत और गुयाना ने एक जैसी गुलामी देखी है। एक जैसा संघर्ष देखा है। आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने यहां और वहां अपनी जान कुर्बान की। आज दोनों देश दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। गुयाना की संसद में मैं भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पीएम ने कहा कि 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का मौका मिला। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गुयाना की विरासत और इतिहास को जानना और समझना था। आज भी गुयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मेरी मुलाकात याद होगी। मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। पीएम ने कहा कि गुयाना ने मुझे कल ही सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का और गुयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां के सभी नागरिकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यह सम्मान भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है- डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमिनिटी फर्स्ट। लोकतंत्र प्रथम की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। मानवता प्रथम की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब मानवता प्रथम को निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता के हित करने वाले ही होते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण का लोकतंत्र से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारे लक्ष्य में है और हमारे आचार-व्यवहार में है। इसलिए जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपने ज20 अध्यक्षता के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य का संदेश दिया।

यह संघर्ष दूर करने का समय- पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लिए यह समय संघर्ष का नहीं है। बल्कि यह समय संघर्ष पैदा करने वाली स्थितियों को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज आतंकवाद, ड्रग्स, साइबर क्राइम, ऐसी कितनी भी चुनौतियां हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें इन मुद्दों का डटकर सामना करना होगा। यह तभी संभव है जब हम लोकतंत्र पहले, मानवता पहले को प्राथमिकता दें।

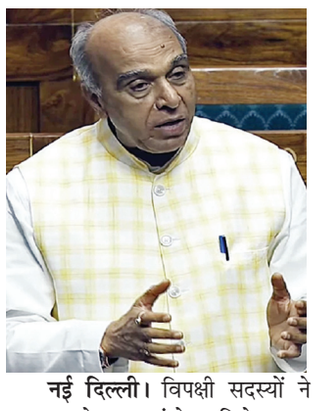

नई दिल्ली। विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के कार्यकाल के विस्तार की मांग करते हुए तर्क दिया कि उन्हें मसौदा कानून में बदलावों का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए। समिति की बैठक में अध्यक्ष और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल ने घोषणा की कि गुरुवार की बैठक पैनल की आखिरी बैठक होगी और एक मसौदा रिपोर्ट शीघ्र ही सदस्यों को वितरित की जाएगी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और उनमें से कुछ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और मामले में उनसे हस्तक्षेप की मांग की। लोकसभा ने समिति को सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गुरुवार को संसदीय सौध में जेपीसी की बैठक हुई। पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह आखिरी बैठक नहीं है। सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया जाएगा तो प्रस्तावित संशोधन पर उनकी राय ली जाएगी और आम सहमति बनाई जाएगी। हमारी रिपोर्ट तैयार है और समिति समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

उम्मीद है कि जेपीसी समिति संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी, जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित के लिए किया जाए। इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की 25 बैठकें हो चुकी हैं। जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित 123 हितधारकों की बात सुनी। यह ध्यान रखना उचित है कि वक्फ अधिनियम, 1995, जो वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था, लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोपों का सामना कर रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को पुन: प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र की शुरुआत करके व्यापक सुधार लाने का प्रयास करता है। जेपीसी सबसे व्यापक सुधार के लक्ष्य के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

वक्फ पर बनी समिति की आज आखिरी बैठक

विपक्ष ने कार्यकाल के विस्तार की मांग की

मुख्यमंत्री ने सपरिवार देखी 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर सुश्री एकता कपूर और फिल्म की नायिका सुश्री रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने 'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है।

कांकेर मत्स्य पालन के लिए मिला बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का राष्ट्रीय अवार्ड

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। आज 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकीय दिवस के अवसर केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायतीराज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल एवं श्री जॉर्ज कुरियन ने छत्तीसगढ़ के मछली विभाग के संचालक श्री नारायण सिंह नाग, सहायक संचालक मछली पालन कांकेर श्री एस.एस. कंवर को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में ट्राफी एवं प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया।

छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश के बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिल चुका है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कांकेर को देश का बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए कांकेर सहित राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ लैंड लॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान पर है। मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का आत्मनिर्भर राज्य है। यह राज्य के मत्स्य कृषकों की मेहनत का परिणाम है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए 2.032 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र है, जिनमें से 96 प्रतिशत में किसी न किसी रूप में मत्स्य पालन हो रहा है। राज्य में प्रतिवर्ष 546 करोड़ मत्स्य बीज तथा 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। यहां से पड़ोसी राज्यों को भी मत्स्य बीज का निर्यात होता है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में देश में 6वें तथा मत्स्य उत्पादन में देश में 8 वें स्थान पर है।

प्रमुख समाचार

कॉप-29 पर गतिरोध: विकसित देशों ने खारिज किया जलवायु वित्त का मसौदा

बाकू। अजरबैजान की राजधानी में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन कॉप-29 के खत्म होने से पहले ही असहमतियों के के बादल मंडराने लगे हैं। विकासशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त पैकेज पर बृहस्पतिवार सुबह जारी किए गए मसौदा प्रस्ताव को सम्मेलन में शामिल दस्तखत करने वाले सभी देशों ने खारिज कर दिया है। कॉप-29 की अध्यक्षता ने स्वीकार किया कि मसौदा अधूरा है और देशों से समझौता प्रस्ताव पेश करने का आग्रह किया। रात तक एक संशोधित मसौदा आने की उम्मीद है, ताकि सहमति बनाने की कोशिश की जा सके। इस साल की यूएन जलवायु वार्ता के केंद्र में नया जलवायु वित्त लक्ष्य या एनसीक्यूजी है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से निपटने में मदद करना है। विकसित देश अभी भी एक अहम सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल है कि 2025 से शुरू होने वाले हर साल से वे विकासशील देशों को कितना जलवायु वित्त देने के लिए तैयार हैं। विकासशील देशों ने बार-बार कहा है कि जलवायु चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं।

राहुल गांधी की प्रेस कॉफ्रेंस में बिजली गुल

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉफ्रेंस में गुरुवार को अचानक बिजली गुल हो गई। इस पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिजली कांग्रेस के ही जयराम रमेश ने काटी होगी। पात्रा ने यह भी कहा कि बिजली चले जाने पर राहुल गांधी अदाणी और दूसरों पर आरोप लगा रहे थे। जबकि उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे लगता है कि उनके पीछे बैठे लोगों ने ही बिजली काटी होगी। मुझे तो जयराम रमेश पर ही शक है। दरअसल राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉफ्रेंस में अदाणी समूह और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। इस दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। कुछ सेकेंड बाद बिजली आई तो राहुल गांधी बोले कि पता नहीं कौन सा अदाणी पावर और मोदी पावर है। हालांकि सब एक है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बिजली गुल हो जाने पर तंज कसा। संबित पात्रा ने कहा कि बिजली चले जाने पर राहुल गांधी अदाणी और दूसरों पर आरोप लगा रहे थे।

ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग, याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) का पंजीकरण रद्द करने और मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप के समान बताया। एआईएमआईएम के सदस्य खुद को एक राजनीतिक दल के रूप में गठित करें। यह याचिका 2018 में अविभाजित शिव सेना के सदस्य, तिरूपति नरसिम्हा मुरारी द्वारा दायर की गई थी। मुरारी ने एआईएमआईएम की मान्यता को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि इसका संविधान केवल एक धार्मिक समुदाय (अर्थात मुसलमानों) के हितों को आगे बढ़ाने के लिए थाऔर इस प्रकार यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका प्रत्येक राजनीतिक दल को संविधान और अधिनियम [जन प्रतिनिधित्व अधिनियम] की योजना के तहत पालन करना चाहिए। ईसीआई ने 1 जून 1992 को पंजीकरण के लिए एआईएमआईएम के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और इसे 2014 में तेलंगाना में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी।

ट्रंप की आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी से चिंता में चीन

बीजिंग। चीन ने अमेरिका की ओर से आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी के बाद अपने निर्यात क्षेत्र को बचाने के लिए नए कदम उठाए हैं। इन कदमों का मकसद सख्त विदेशी व्यापार प्रतिबंधों का मुकाबला करना और अपने निर्यात के अनुकूल माहौल तैयार करना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया था और चीन के निर्यात पर शुल्क लगाए थे। अब एक बार फिर उन्होंने इन शुल्कों को 60 फीसदी तक बढ़ाने की चेतावनी दी है। इससे चीन के निर्यात पर गंभीर असर पड़ सकता है। बीजिंग को अमेरिका के साथ व्यापार में लाभ मिलता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये नए नीतिगत कदम कंपनियों को सख्त विदेशी व्यापार प्रतिबंधों का सक्रिय रूप से मुकाबला करने और निर्यात के लिए अच्छा माहौल बनाने में मदद करेंगे। बीजिंग की ओर से जारी किए गए नौ बिंदुओं के नए दस्तावेज में विदेश व्यापार में स्थिरता को बढ़ावा देने और सकारात्मक आर्थिक विकास को फिर से हासिल करने के उपायों को मजबूत करने का जिक्र किया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी समकक्ष से मिले

वियनतियाने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड जे ऑस्टिन ने लाओस के वियनतियाने में मुलाकात की और परिचालन समन्वय, सूचना-साझाकरण और औद्योगिक सहयोग और नवाचार में वृद्धि पर जोर देते हुए भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी में प्रभावशाली प्रगति की सराहना की। रक्षा मंत्रालय ने न्यू में जारी एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने अमेरिका-भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप के तहत की गई उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी, जिसमें जेट इंजन, युद्ध सामग्री और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम के लिए प्राथमिकता वाले सह-उत्पादन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चल रहा सहयोग शामिल है। सिंह और ऑस्टिन ने 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (एडीएमएम)-प्लस से इतर बातचीत की। पिछले साल अपनाया गया रोडमैप, हवाई युद्ध और भूमि गतिशीलता प्रणाली, खुफिया, निगरानी और टोही, युद्ध सामग्री और पानी के नीचे के क्षेत्र सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तेजी से प्रौद्योगिकी सहयोग और सह-उत्पादन करना चाहता है।

गौतम अदाणी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने व धोखाधड़ी के आरोप

नई दिल्ली। अमेरिकी अभियोजकों ने अदाणी (62), उनके भतीजे सागर अदाणी और अन्य पर सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत देने का आरोप लगाया। एक अनुमान के अनुसार इससे समूह को संभावित रूप से दो अरब डॉलर से अधिक का लाभ हो सकता है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यह सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया, जिनसे अदाणी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। अदाणी समूह से इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।

अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने अदाणी समूह के खिलाफ क्या कहा?

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने बयान में कहा, ''प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत साजिश रची।'' विभिन्न कारोबारों से जुड़े अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी, उनके भतीजे एवं अदाणी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी और कंपनी के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रहे विनीत जैन पर प्रतिभूति धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और वायर धोखाधड़ी की साजिश का आरोप लगाया गया है। अदाणी पर अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के एक दीवानी मामले में भी आरोप लगाए गए हैं। अभियोग में सागर और जैन पर संघीय कानून तोड़ने के भी आरोप लगाये गये हैं।

अदाणी के खिलाफ ताजा विवाद कनाडा से कैसे जुड़ा है?

अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड सीडीपीक्यू के तीन पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया कि उन्होंने ई-मेल 'डिलीट' कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए सहमत होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा डाली। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला सीडीपीक्यू अदाणी समूह की कंपनियों में शेयरधारक है।

समूह पर असर

अदाणी समूह पर ये आरोप उसे फिर से समस्याओं में डाल सकता है। इससे पहले, अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाये थे, जिससे वह अभी उबरा ही था। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में शेयरों में हेराफेरी और लेखा के स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाये थे। अदाणी समूह ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया था।

इन आरोपों के कारण समूह के बाजार मूल्यांकन में 150 अरब डालर का नुकसान हुआ था। हालांकि समूह उससे उबर गया और कंपनियों के शेयरों में जो नुकसान हुआ था, उसकी काफी हद तक भरपाई कर ली गयी। अदालत के दस्तावेज के अनुसार, ''विशेष रूप से 17 मार्च 2023 को या उसके आसपास एफबीआई (संघीय जांच ब्यूरो) के अधिकारियों ने अमेरिका में सागर अदाणी से संपर्क किया और तलाशी वारंट के तहत उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया।''

'न्यूमैरो उनो' और 'द बिग मैन' कोड

दस्तावेज के अनुसार, साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अदाणी को निजी तौर पर 'न्यूमैरो उनो' और 'द बिग मैन' कोड नामों से बुलाते थे। वहीं उनके भतीजे कथित तौर पर रिश्वत के बारे में विशिष्ट जानकारी पर नजर रखने के लिए अपने सेलफोन का इस्तेमाल करते थे। जिन अन्य लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, उनमें रंजीत गुप्ता और रूपेश अग्रवाल शामिल हैं। ये क्रमश: एज्यूर पावर ग्लोबल के पूर्व सीईओ और पूर्व मुख्य रणनीति एवं वाणिज्यिक अधिकारी हैं। इनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वे कुछ रिश्वत देने के लिए सहमत हुए थे। शिकायत में उन पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और स्थायी रूप से रोक, जुर्माना समेत अन्य प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।

अमेरिकी निवेशकों से संबंध

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) ने बयान में कहा कि कथित साजिश के तहत अदाणी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक जुटाए और एज्यूर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। इसके साथ ही, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अदाणी, सागर अदाणी, सिरिल कैबनेस और अदाणी ग्रीन तथा एज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाये हैं। ब्रूकलिन की एक संघीय अदालत में मामला दर्ज किया गया है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़े रिश्वत मामले में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश के लिए पांच अन्य लोगों पर आरोप लगाये गए हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने विश्व मात्स्यिकी दिवस दी बधाई और शुभकामनाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्यपालन से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि विश्व भर में सभी मत्स्यपालकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मत्स्यपालन के क्षेत्र में सतत और न्यायसंगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मत्स्यपालन के क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा समान और समावेशी विकास लाने की अपार संभावनाएं है। हमारा प्रदेश भी नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालकों के सशक्तिकरण और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा हैं। यह मछली पालकों को स्थायी आय और आजीविका प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

साय ने गुयाना देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर मोदी को दी बधाई

रायपुर। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को गुयाना देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान-द आर्डर आफ एक्सीलेंस- और डोमिनिका देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान-डोमिनिका अवार्ड आफ आनर- से सम्मानित किया जाना 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक्स पर लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है। यह सम्मान भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और अधिक मजबूती देता है। समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन।

जैन दादाबाड़ी में आयोजित दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित हुए राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका गत दिवस

रायपुर के जैन दादाबाड़ी में आयोजित पंच दिवसीय दीक्षा महोत्सव में विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने वहां स्थित मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और उपस्थित तपस्वी जैन मुनियों से प्रदेश की सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने 12 कठिन व्रतों के साथ आत्मशुद्धि की क्रिया को मुमुक्षुओं द्वारा मानवता के लिए की जा रही कठोर तपस्या बताते हुए उनके त्याग और समर्पण को नमन किया। महोत्सव में रायपुर (उत्तर) विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग उपस्थित रहे।

सुधा सोसाइटी फाउंडेशन ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस पर लोगों का किया सम्मान

रायपुर। सुधा सोसाइटी फाउंडेशन ने

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाते हुए समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले दो वरिष्ठ पुरुष जनों श्री शुभांशु खरे और श्री कौशल चौधरी का सम्मान किया। यह जानकारी सुधा फांउडेशन के चेयरमैन श्री गोपाल कृष्ण भटनागर ने दी। उन्होने बताया कि 19 नवंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया भर में पुरुषों द्वारा अन्य परिवारों और समुदायों में लाए गए सकारात्मक मूल्य के लिए विश्व भर में मनाया जाता है । हम सकारात्मक रोल मॉडल को उजागर करते हैं और पुरुषों की भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। 2024 के लिए आज का विषय सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल है। सुधा फांउडेशन की ओर से ऐसे दो प्रमुख शख्सियतों का सम्मान किया गया जिन्होंने समाज में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। इनमें राजधानी रायपुर के शुभांशु खरे और श्री कौशल चौधरी हैं का सम्मान किया गया। सुभांशु खरे ,मित्सुबिशी कंपनी के रीजनल मैनेजर है ओर आर्ट ऑफ़ लिवंग के फैकल्टी हैं वहीं कौशल चौधरी व्यापार जगत से जुड़े समाजसेवी कार्यकर्ता हैं। इन दोनों शख्सियतों का सम्मान सुधा फांउडेशन की ओर से डॉ एमजी नायडू के भटनागर ने किया। इस अवसर पर एवं इंद्रदेव सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

बलौदा बाजार। बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट

परिसर में 10 जून को हुई हिंसा एवं आगजनी मामले में पुलिस ने एक अन्य फरार आरोपी आशीष टंडन बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कलेक्टर परिसर में तोड़फोड़ एवं आगजनी करते आरोपी की पहचान हुई थी। इस मामले में अभी तक कुल 187 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।

बिटकॉइन घोटाले में भूपेश और कांग्रेस नेता अपनी भूमिका पर जनता को जवाब दें : भाजपा

इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व हैं और अपराध करने वाला छत्तीसगढ़ में है, तो क्या इसमें भूपेश भी इन्वॉल्व हैं?

रायपुर। बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि बिटकॉइन मामले में, जिसके तार महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्री श्रीवास्तव ने पुरजोर मांग की कि बिटकॉइन घोटाले मामले में भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अपनी भूमिका पर प्रदेश की जनता को जवाब दें।

श्रीवास्तव ने गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रही एक नेत्री ने एक्स पोस्ट कर यह पूछा है कि बिटकॉइन मामले में लिप्त जिस गौरव मेहता के यहां छत्तीसगढ़ में कारवाई हुई है, उसके पूर्व सीएम भूपेश बघेल से क्या संबंध थे? महादेव ऐप मामले में तो यह स्पष्ट ही हुआ है कि कांग्रेस सरकार

में आर्थिक मामलों के तार अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े रहे हैं, ऐसे में बिटकॉइन घोटाले का यह खुलासा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को, खासकर भूपेश बघेल को इसका जवाब देना चाहिए।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले जो ऑडियो टेप सामने आया है, उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बातचीत भी है। अगर इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व है और अपराध करने वाला छत्तीसगढ़ में है, तो यह क्यों न माना जाए कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस और इस प्रकार के कार्यों में महारत रखने वाले भूपेश बघेल इन्वॉल्व हैं? इससे पहले भी राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस को भ्रष्टाचार के रुपयों से फंडिंग करने के तथ्य सामने आ चुके है। भ्रष्टाचार के हर आरोपी के साथ छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल का इनवॉल्वमेंट पाया गया है, फिर वह सौम्या चौरसिया हो, समीर विश्नोई हो, एजाज ढेबर के भाई अवनर ढेबर हो या कोई और।

श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साक्षी है कि कांग्रेस की भूपेश-सरकार किस तरह अनेक गंभीर आर्थिक आपराधिक मामलों में लिप्त रही है! भाजपा ने लगातार उन विषयों को उठाया और प्रदेश देख रहा है कि भूपेश-सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं को किसी भी अदालत से जमानत तक नहीं मिल पा रही है। ताज़ा मामला पीएससी के अध्यक्ष रहे टामन सोनवानी का है।

5 साल तक लगातार भाजपा उनके घोटाले के खिलाफ आवाज उठाती रही। यह अपनी तरह की एक अनोखी सरकार थी जो अपने ही राजस्व पर डाका डालती रही। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आज भूपेश बघेल के कई करीबी या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, समीर बिश्नोई, भूपेश बघेल के चहेते महापौर के भाई एजाज ढेबर पर जब-जब एजेंसियां कार्रवाई करती रही भूपेश बघेल उनके संरक्षक बनकर खड़े होते रहे और इसे पॉलिटिकल मामला बताते रहे। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि महीनों हो गए, अदालत से इन्हें बेल नहीं मिलना इस बात का सबूत है कि ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उनके संरक्षक पिछली कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया भूपेश बघेल थे। सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं परंतु, सभी भ्रष्टाचार में कांग्रेसियों के नाम ही क्यों आ रहे हैं, यह अवश्य शोचनीय है।

प्रेस ब्रीफ के दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी अनुराग अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता द्वय उमेश घोरमोड़े और अमरजीत छाबड़ा भी मौजूद रहे।

दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री साय छत्तीसगढ़ को मिली कई सौगातें

रायपुर. सीएम साय गुरुवार को अपने दो दिवसीय दिल्ली दौरे से वापिस राजधानी लौटे। वापसी के बाद सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अपने दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री से की मुलाकात की। इसमें छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिली है।

सीएम साय ने बताया कि बुधवार को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृहमंत्री शाह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में बस्तर चल रहे ओलम्पिक के समापन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवॉर्ड घोषित हुआ है, जिसका समारोह भव्य होता है, उसमें भी शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की आग्रह किया है। दोनों कार्यकम में आने के लिए उन्होंने सहमति दी है।

वहीं सीएम साय ने कहा- बुधवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात किए। प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, उसके विषय में अवगत कराया। उनसे बड़ी सार्थक चर्चा हुई। जल्द ही प्रदेश और केंद्र के अधिकारियों की बैठक होगी। हमने मांग रखा है कि रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशन एयरपोर्ट बनाया जाए। यह इंटरनेशन कार्गो बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट का इंनोग्रेशन किया है, वहां फ्लाइट चालू किया जाए। आने वाले 15 दिसंबर से रायपुर से अंबिकापुर फ्लाइट की शुरुवात हो रही है। बिलासपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है। उन्होंने आश्वास्त किया है कि जल्द ही इसकी भी शुरुवात होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी राची से हवाई सुविधा कनेक्टिविटी हो इसकी भी मांग रखी है। विश्वाश है कि वे छत्तीसगढ़ की चिंता करेंगे।

वहीं क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ईडी ने रायपुर में दबिश दी है। इस मामले में भूपेश बघेल के तार गौरव मेंहतो से जुड़ने की चर्चा हो रही है। इसे लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि जांच में किसके तार कहां जुड़े हैं सामने आ जाएंगे। कोई बक्शे नहीं जाएंगे।

गुवाहाटी में अभा विद्युत महिला खेल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ को मिला 8 पदक

मुख्यमंत्री साय, कंपनी अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने दी बधाई

रायपुर। 46वीं अखिल भारतीय विद्युत महिला स्पर्धा में छत्तीसगढ़ महिला टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टीम इवेंट में टेबल टेनिस व शतरंज में रजत, बैडमिंटन में कांस्य व व्यक्तिगत स्पर्धाओं को मिलाकर 8 पदक हासिल करने में कामयाब रही। समापन समारोह में असम की ऊर्जा एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती नंदिता गोर्लोसा ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री श्री विष्णुदेव साय, पॉवर कंपनी अध्यक्ष व ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के दल को बधाई देते हुए कहा है कि इनके उम्दा प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं का झण्डा गाडने के लिए इसी प्रकार लगन और निष्ठा से अभ्यास करते रहना चाहिए।

गुवाहाटी असम में 17-20 नवंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने अलग-अलग श्रेणी में पदकों पर अपना कब्जा जमाया। टीम की मैनेजर श्रीमती अनामिका मण्डावी ने बताया कि टेबल टेनिस स्पर्धा में टीम इवेंट में (दिव्या आमदे, श्रद्धा वर्मा,

शिखा खाण्डे, शोभना सिंह) द्वारा रजत पदक हासिल किया गया, सिंगल्स में दिव्या आमदे द्वारा स्वर्ण एवं डबल्स में श्रद्धा व दिव्या की जुगलबंदी को रजत पदक प्राप्त हुआ।

इसी तरह बैडमिंटन में (संध्या रानी, जुवेना गोम्स, वीरांगना भगत, श्रद्धा पिल्लई) द्वारा टीम इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त हुआ, सिंगल्स में संध्या रानी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। शतरंज स्पर्धा में टीम इवेंट में नूतन ठाकुर, मीना कुर्रे, सानिली चौहान, भारती फेराओ ने रजत पदक दिलाया, प्रथम बोर्ड प्राइस में नूतन ठाकुर, चौथी बोर्ड प्राइस भारती फेराओ को मिला। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की महिला खिलाड़ियों ने पांच स्पर्धाओं (टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, टेनिकोइट) के लिए राष्ट्रीय स्तर के 8 स्टेट टीमों से मुकाबला कर तीन स्पर्धा में कुल 8 पदक प्राप्त किये।

छत्तीसगढ़ महिला खिलाड़ियों को टीम मैनेजर श्रीमती अनामिका मांडवी, कोच श्री सागर पिंपलापुरे के द्वारा पूरे टूर्नामेंट मे मार्गदर्शन मिलता रहा। इस अवसर पर ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट श्री सुरेश कैमल, महासचिव श्री के. शिव कुमार, वरिष्ठ खेल अधिकारी श्री टी.कुमार वेदुवालु, खेल अधिकारी श्री एम.एस. नायडू, उप. महा. प्रबंधक वित्तीय श्रीमती पूर्वी नाथ उपस्थित थे।

अभा विद्युत लॉन टेनिस स्पर्धा 23 से रायपुर में

9 प्रदेशों के खिलाड़ी आएंगे, समापन 25 को

रायपुर। 46वीं अखिल भारतीय विद्युत लॉन टेनिस स्पर्धा का आयोजन 23 से 25 नवंबर तक राजधानी में किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की केंद्रीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति इसकी मेजबानी कर रही है। इसमें विभिन्न प्रदेशों की विद्युत कंपनियों की नौ टीमें हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ रोहित यादव समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे।

स्पर्धा का उद्घाटन समारोह 23 नवंबर को 11.30 बजे छछानपैरी स्थित एपीआईसीईएम टेनिस कोर्ट में होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार होंगे तथा प्रबंध निदेशकगण श्री राजेश कुमार शुक्ला एवं श्री भीमसिंह कंवर

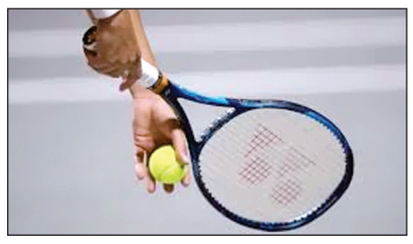

विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह 25 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे होगा, जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव होंगे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में प्रबंध निदेशकगण श्री राजेश कुमार शुक्ला एवं श्री भीमसिंह कंवर उपस्थित रहेंगे।

पॉवर कंपनीज के अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र ने बताया कि हर राज्य की विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कंपनियां अपने कर्मियों के लिए प्रतिवर्ष क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्पर्धाओं के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं का आयोजन अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण मंडल करती है। इस बार अखिल भारतीय लॉन टेनिस स्पर्धा की मेजबानी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की केंद्रीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति को दी गई है। इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ सहित आंध्रप्रदेश, असम, कर्नाकट, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कोलकाता, तेलंगाना राज्य से विद्युत कंपनियों की टीमें शामिल होंगी।

सीबीएसई ने पहली बार 86 दिन पहले जारी किया परीक्षा तिथि

रायपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहली बार 86 दिन पहले चालू शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए 10-12वीं कक्षा की विषय वार परीक्षा समय सारिणी जारी कर दी है। सभी अभ्यर्थी अपने विषय के अनुसार समय सारिणी चेक कर सकते हैं। बोर्ड में परीक्षाओं के अंदर दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया है जिससे विद्यार्थी अपनी विषय की तैयारी अच्छे से कर सकें। मूल्यांकन के दौरान सभी विषयों के शिक्षक एक साथ तथा अधिक समय तक स्कूल से दूर नहीं रहेंगे।

सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं कक्षा के पर्चे सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 तक लिखे जा सकेंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थी की 75 प्रतिशत अटेंडेंस होना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी की अटेंडेंस स्कूल में 75 फीसदी से कम होती है तो वह बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। सीबीएसई की गाइडलाइंस में कहा गया है की बोर्ड कुछ मामलों में 25 प्रतिशत की छूट दे सकता है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी, राष्ट्रीय खेलों में हिस्सेदारी या फिर अन्य कोई गंभीर वजह इस राहत को पाने के

लिए विद्यार्थी को संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।

सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड डेट शीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य वेबसाइट पर जाना है इसके बाद होम पेज पर लेटेस्ट ऑप्शन में 10वीं और 12वीं क्लास डेट शीट 2025 के लिंक पर क्लिक करना है जिससे दसवीं और बारहवीं कक्षा का टाइम टेबल स्क्रीन पर खुल जाएगा अब अभ्यर्थी अपनी कक्षा और विषय के अनुसार टाइम टेबल चेक कर सकते हैं।

रायपुर रेंज में ढाई करोड़ की शराब पर चला पुलिस का बुलडोजर

बलौदाबाजार में 34 हजार लीटर, महासमुंद में 12 हजार 117 लीटर, रायपुर में 33 हजार लीटर से अधिक शराब का नष्टिकरण

रायपुर/बलौदाबाजार/महासमुंद। रायपुर रेंज में आज जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रेंज के तीनों जिलों में करीब 80 हजार लीटर अवैध शराब नष्ट की गई है। बताया जा रहा है कि करीब ढाई करोड़ रुपये के कीमत की बड़ी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया है।

बलौदाबाजार में 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण

बलौदाबाजार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने दाहोद स्थित पुलिस लाइन के पीछे खुले मैदान में करीब 34 हजार लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण किया। यह कदम जिला

कलेक्टर के निर्देश पर उठाया गया, क्योंकि थानों में जब्त शराब रखने के लिए अब जगह नहीं बची थी। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि यह शराब पिछले 10-12 वर्षों में जिले में अवैध शराब के मामलों में जब्त की गई थी। नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। पुलिस ने न्यायालय से विधिवत परमिशन लेकर यह कार्रवाई की। इस नष्टिकरण में 1934 प्रकरणों में जब्त की गई शराब को नष्ट किया गया। इससे पहले मई माह में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।

महासमुंद में 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब का नष्टिकरण

महासमुंद जिले के परसदा पुलिस लाइन में भी अवैध शराब का नष्टिकरण किया गया। यहां पर 12 हजार 117 लीटर अवैध शराब नष्ट की गई, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है। यह शराब वर्ष 2013 से लेकर अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त की गई थी। न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस ने शराब को नष्ट किया, जिसमें महुआ, देशी और अंग्रेजी शराब शामिल थी।

रायपुर में 33 हजार लीटर से अधिक शराब का नष्टिकरण

रायपुर में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर, राजधानी पुलिस ने 33,532 लीटर अवैध शराब नष्ट की, जिसकी कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपये है। इस कार्रवाई के दौरान एसएसपी संतोष सिंह, एडीएम देवेंद्र पटेल समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, कबीरधाम (छ.ग.)

नि.क्र. 09/ले.शा./ (निविदा) / का.अ./ लो.स्वा.यां.वि. खड/2024 कबीरधाम दिनांक 19/11/29

// मैनूअल पद्धति निविदा सूचना //

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से लोक स्वास्थ्य यौंत्रिकी खण्ड कबीरधाम के अंतर्गत नीचे लिखे कार्य हेतु समुहवार निविदा निम्न समय सारिणी अनुसार सामग्री के निर्माता एवं अधिकृत विक्रेता से प्रपत्र स में निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिये खण्ड कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 02.12.2024 समय 5:30 बजे तक।

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 03.12.2024 समय 5:30 बजे तक।

समूह क्र.	कार्य का विवरण	अनु. लागत (रू. लाख में)
1	कबीरधाम जिले के उपखण्ड कवर्धा अंतर्गत हैण्डपंपों के संधारण एवं संचालन हेतु सामग्री का प्रदाय कार्य (शेड्यूल 01 के अनुसार)	4.75
2	कबीरधाम जिले के उपखण्ड कवर्धा अंतर्गत हैण्डपंपों के संधारण एवं संचालन हेतु सामग्री का प्रदाय कार्य (शेड्यूल 02 के अनुसार)	4.45

उपरोक्त कार्य की निविदा में भाग लेने की पात्रता, सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय कार्यपालन अभियंता लो.स्वा.यां.खंड कबीरधाम से प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
कबीरधाम (छ.ग.)

जी-242503902/4

बिटकॉइन घोटाला : महाराष्ट्र चुनाव का पलट देगा पूरा खेल?

अभिनय आकाश

महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग से महज एक रात पहले प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्र नाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बिटकॉइन घोटाले के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें बारामति की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हैं। वो पहले ही 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बेच चुके हैं। उनके पास कई सौ करोड़ के बिटकॉइन और भी हैं। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने 19 नवंबर को रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीलर अभिताभ गुप्ता औऱ सुप्रिया सुले-नाना पटोले के बीच की बातचीत का एक वीडियो शेयर किया औऱ पूछा कि डीलर जिनकी बात कर रहा है वो बड़े लोग आखिर कौन हैं? इन सब के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये आरोप सिरे से गलत है और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानी का केस करने जा रही हूं। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ? वोटिंग से एक रात पहले इस तरह के आरोपों के पीछे का सच क्या है और जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। रवींद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि शरद पवार की बेटी सुले और राज्य कांग्रेस प्रमुख पटोले ने 2018 के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन का दुरुपयोग किया था और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनावों में फंडिंग के लिए किया था। उनका कहना है कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुणे के तत्कालीन पुलिस आयोग अमिताभ गुप्ता और साइबर अपराध जांच को संभालने वाली तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नौताके बिटकॉइन के दुरुपयोग में शामिल थे। पुणे पुलिस ने साइबर विशेषज्ञ पंकज घोडे के सहयोग से 2018 में दायर कुछ क्रिप्टोकरेंसी मामलों की जांच के लिए पाटिल को नियुक्त किया था। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान पाटिल ने कुछ क्रिप्टोकरेंसी अपने खाते में स्थानांतरित कीं। घोडे ने पुलिस को खातों के स्क्रीनशॉट दिए, जिससे पता चला कि क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में पैसे कम थे। हालांकि, पाटिल ने दावों का खंडन किया और संवाददाताओं से कहा कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने इस पर गौर किया है। उन्होंने दावा किया कि मामले के मुख्य गवाह और ऑडिट फर्म के कर्मचारी गौरव मेहता ने उन्हें 2018 बिटकॉइन धोखाधड़ी जांच के बारे में सूचित किया था। मेहता ने दावा किया है कि जब क्रिप्टोकरेंसी डीलर अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था तो एक बिटकॉइन युक्त हार्डवेयर वॉलेट लिया गया था। हालाँकि, कथित तौर पर उस समय पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के आदेश पर इसके स्थान पर एक अलग वॉलेट का इस्तेमाल किया गया था। सुले के चचेरे भाई और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्वीकार किया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक आवाज सुले की थी और कहा कि घटना की जांच शुरू की जानी चाहिए। आरोप सामने आने के तुरंत बाद, भाजपा ने मीडिया में ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की और दावा किया कि वे बिटकॉइन घोटाले में पटोले और सुले की संलिप्तता के सबूत हैं। फर्स्टपोस्ट स्वतंत्र रूप से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सुले और पटोले पर महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के पक्ष में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए अवैध बिटकॉइन लेनदेन से जुड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। शाम को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में त्रिवेदी ने कहा कि एक आरोपी डीलर एक पूर्व पुलिस अधिकारी से संपर्क करता है, जो पहले जेल जा चुका है और उसे बताता है कि वह (डीलर) नकद में बिटकॉइन लेनदेन करना चाहता है। अधिकारी ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया। हालांकि, डीलर ने कथित तौर पर नाना पटोले और सुप्रिया सुले का नाम लेते हुए दावा किया कि कुछ 'बड़े लोग' इसमें शामिल हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब अधिकारी संदेह व्यक्त करता है, तो डीलर उसे ऑडियो क्लिप भेजता है।

बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच जी-20

प्रो अश्विनी महाजन

पिछले वर्ष भारत ने जी-20 समूह के अध्यक्ष के नाते जी-20 सम्मेलन आयोजित किया था। कई मायनों में वह सम्मेलन अभूतपूर्व था। खासतौर पर वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्ष और युद्ध के वातावरण के बावजूद आम सहमति से घोषणा पत्र जारी किया गया था। भारत से पूर्व इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी, लेकिन तब अंतिम घोषणापत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस की आलोचना की गयी थी।

भारत में जी-20 सम्मेलन बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। इसकी न सिर्फ भौतिक तैयारियां, बल्कि बौद्धिक तैयारियां भी पूरी गंभीरता से की गयी थीं। वर्ष 2023 के सम्मेलन में भारत द्वारा रूस के बारे में कुशलतापूर्वक न केवल विवादास्पद भाषा से बचा जा सका, बल्कि विश्व के समक्ष उपस्थित मुद्दों, खासतौर पर बहुपक्षीय विकास बैंकों समेत वैश्विक वित्तीय संस्थानों में पूंजीगत संरचना में बदलाव, क्रिप्टो करेंसी, वैश्विक ऋण संबंधी समस्याओं का प्रबंधन, मौसम परिवर्तन से जुड़े वित्तीयन के मुद्दे आदि-सभी पर खुली चर्चा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। 'वसुधैव कुटुंबकमं' के आधार पर 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के ध्येय वाक्य ने वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्षों, समस्याओं, मुद्दों को जैसे एक सूत्र में पिरो दिया था।

ब्राजील की राजधानी रियो में संपन्न जी-20 सम्मेलन में इन विषयों को आगे ले जाने की एक विशेष चुनौती थी, इसलिए इसमें हुई चर्चाओं और सहमतियों को उस आलोक में भी देखना महत्वपूर्ण है। सम्मेलन की थीम थी 'एक न्यायपूर्ण विश्व और एक धारणीय ग्रह।

जी-20 सम्मेलन भारत से प्रेरित

ब्राजील की राजधानी रियो में संपन्न जी-20 सम्मेलन में इन विषयों को आगे ले जाने की एक विशेष चुनौती थी, इसलिए इसमें हुई चर्चाओं और सहमतियों को उस आलोक में भी देखना महत्वपूर्ण है। सम्मेलन की थीम थी 'एक न्यायपूर्ण विश्व और एक धारणीय ग्रह'। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने कहा भी कि यह सम्मेलन पिछले वर्ष की भारत की अध्यक्षता से प्रेरित रहा। सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने सदस्य राष्ट्रों को अपने पर्यावरण लक्ष्यों को बढ़ाने का आह्वान किया। सम्मेलन के घोषणापत्र में पर्यावरण वित्त पर गतिरोध खत्म करने की जरूरत पर बल दिया, पर उसके समाधान के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन देने में यह घोषणापत्र विफल रहा। पर्यावरण वित्त पर यह गतिरोध लगातार बना हुआ है, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन जैसे अत्यंत गंभीर मुद्दों पर विकसित देशों की संवेदनहीनता भी दर्शाता है।

हालांकि सम्मेलन का घोषणापत्र यह कहता है कि पर्यावरणीय वित्त को सभी स्रोतों से अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और पर्याप्त रूप से बढ़ाना जरूरी है, पर इसके बारे में ठोस रणनीति या संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं देती। यह चिंतनीय है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने संबंधी भी कोई बात घोषणापत्र में नहीं आ पायी। दरअसल जीवाश्म ईंधन का उपयोग समाप्त करने पर पूरा विश्व एकमत नहीं है। हालांकि दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन में देशों ने जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने संबंधी सहमति दर्शायी है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं को यह लगता है कि जी-20 घोषणापत्र में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के बारे में बात न आने से कॉप-29 में यह मुददा कमजोर पड़ जाएगा।

भारत में 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए

सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे, 55 करोड़ लोग फ्री हेल्थ बीमा का लाभ उठा रहे, किसानों को 20 बिलियन डॉलर (168 हजार करोड़ रुपये) दिए गए। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है।'

प्रधानमंत्री के भाषण में पिछले सम्मेलन की थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' का जिक्र आया और उन्होंने इसे इस सम्मेलन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक बताया। यही नहीं, उन्होंने जी-20 सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की बात भी रखी। समझना होगा कि यह जी-20 के लिए एक मील का पत्थर था। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया में खाद्य, तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ है और विकासशील राष्ट्रों पर इसका असर सबसे ज्यादा हुआ है।

किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं रहता। सम्मेलन के साथ-साथ यह एक अवसर भी होता है कि अन्य मुल्कों के साथ महत्वपूर्ण मुददों पर बातचीत हो, कुछ अनसुलझे मुददे सुलझाये जाएं, मित्र देशों के साथ अपनी प्रगाढ़ता बढ़ायी जाए और विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों के साथ सीधी बातचीत से देश के हितों को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री एवं प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न सदस्यों ने इस मौके का बखूबी इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल ब्राजील के राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जियोंजिया मेलोनी के साथ मिलकर प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे मुददों पर बातचीत की गयी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन के साथ भी उनकी मुलाकात चर्चा में रही। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्ट्रॉमर के साथ भी प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार जैसे मुददों पर बातचीत हुई और इन मुददों पर मिलकर काम करने पर बल दिया गया। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को पुनः शुरू करने की बात भी की गयी। इसके अलावा फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया के नेताओं के साथ भी सार्थक द्विपक्षीय बातचीत हुई।

भारत-चीन संबंध बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी

एक अन्य दिलचस्प बात यह कि भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत अच्छी रही। भारत-चीन सीमा पर दो विवादास्पद ठिकानों पर सेनाओं के पीछे हटने के फैसले के बाद यह पहली बार हुआ कि चीन के साथ सीमा विवादों पर कोई सरकारी बातचीत हुई। समझा जा सकता है कि इससे भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे और इस क्षेत्र में स्थायित्व आएगा। गौरतलब है कि मई, 2020 से शुरू होते हुए पिछले चार साल से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी बनी हुई है।

ऐसा लगता है कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से अस्तित्व में आए जी-20 समूह का वैश्विक महत्व पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ता ही गया है। विभिन्न देश इस सम्मेलन में शासनाध्यक्षों की उपस्थिति द्वारा प्रदत्त अवसर को अत्यंत गंभीरता से विभिन्न मुद्दों के बारे में आम सहमति बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी-20 सम्मेलन हो या ब्रिक्स सम्मेलन, वैश्विक स्तर पर इनके बढ़ते महत्व को समझते हुए कूटनीति विशेषज्ञ इन्हें महत्वपूर्ण वैश्विक मंच मानने लगे हैं। इसके जरिये नए समीकरण भी बन रहे है। युद्ध, आर्थिक चुनौतियों और विभिन्न संघर्षों के समय इन मंचों का उपयोग विश्व शांति, पर्यावरणीय समस्याओं, राजकोषीय चुनौतियों, प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए करना निस्संदेह वक्त की मांग है।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्याय:

गतांक से आगे...

(8) तैत्तिरीयारण्यक (भाष्य 2।6) में सायणाचार्य जी लिखते हैं गाथा मन्त्रविशेषा: अर्थात् मन्त्रविशेष का नाम गाथा है । सो केवल गन्त्र वेद में ही होते हैं। अत: निश्चय हुआ कि ब्राह्मण नेद हैं ।

(9) पातञ्जल महाभाष्य में लिखा है कि -वेदे खल्वपि- पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिक्षाव्रतो वैश्य इत्युच्यते । (महा0 1।1।1)

अर्थात्- वेद में लिखा है कि ब्राह्मण पयोव्रत होते हैं। क्षत्रिय यवागू व्रत होते हैं और वैश्य थामिक्षाव्रत होते हैं। उपरोक्त पयोव्रत आदि वाक्य मन्त्रभाग में कहीं भी नहीं, बल्कि यह ब्राह्मणभाग का वाक्य है। पतञ्जलि जी इसे वेदवाक्य कहते हैं अत: निश्चित हुआ कि उनकी दृष्टि में ब्राह्मण वेद हैं।

(10) इसी ग्रन्थ के दूसरे स्थान में लिखा है कि- वेदशब्दा अप्येवमभिवर्दान्त योऽग्निष्टोमेनयजतेय उचैनमेवं वेद। (पृ010)

अर्थात्- वेद भी ऐसा कहते हैं कि- जो अग्निष्टोम यज्ञ द्वारा यजन करता है, और जो इसे ऐसा जानता है ।

यहाँ भी जो योऽग्निष्टोमेन आदि वाक्य लिखा है वह मन्त्रभाग का नहीं, बल्कि तैत्तिरीय ब्राह्मण (3।11।8।5) का है। परन्तु पतञ्जलि महाराज इसे वेदशब्द के नाम से स्मरण करते हैं अत: निश्चित हुआ कि उनके मत से भी ब्राह्मण वेद हैं।

(11) मनु जी लिखते हैं-एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वन्। विविधाश्चोपनिषदोरात्मसंसिद्धये श्रुती:।। (मनुस्मृति 6 । 26)

अर्थात्- वन में रहता हुआ ब्राह्मण ऐसी धार्मिक दीक्षाओं का सेवन करे और अपने कल्याण के लिये विविध उपनिषद् ग्रन्थों की श्रुति का सेवन करे।

यहां ब्राह्मणान्तर्गत उपनिषद्-वाक्यों को श्रुति कहा है।

क्रमश: ...

दुर्गादास राठौड़ जिन्होंने औरंगजेब के बेटे को अपनी तरफ मिलाकर दी थी चुनौती

मुगलों के सबसे क्रूर शासक कहे जाने वाले औरंगजेब को जिन योद्धाओं ने चुनौती दी उनमें एक नाम दुर्गादास राठौड़ का भी शामिल था। मारवाड़ के राजपूत योद्धा दुर्गादास की वीरता और ईमानदारी के किस्से पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। औरंगजेब को शिकस्त देने के लिए इन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई कि उसका बेटा मुहम्मद अकबर तक खुद इनके पाले में आ गया।

दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में हुआ। इनके पिता आसकरण जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते थे। मां और पिता के बीच मतभेद रहे और दुर्गादास के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए। बड़े हुए तो मां के साथ लूणवा गांव में खेती करने लगे।

महाराज जसवंत सिंह की मौत दिसंबर 1678 में उस समय हुई जब वो अफगानिस्तान में थे। उनका कोई वारिस नहीं था, लेकिन उनकी मौत के कुछ समय बाद ही उनकी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरा बच्चे का नाम अजीत सिंह था, जिसे उत्तराधिकारी माना जा रहा था,

लेकिन औरंगजेब ने बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं माना। औरंगजेब ने मेवाड़ की स्थिति को एक मौके के तौर पर देखा। मुगल बादशाह ने कब्जा करके राज्य को सरदार इंद्र सिंह को बेच दिया और दिल्ली वापस आ गया।

दुर्गादास राठौर और मारवाड़ के कई प्रमुख लोग अजीत सिंह को वारिस घोषित कराने के लिए औरंगजेब के पास पहुंचे। औरंगजेब चाहता था कि अजीत सिंह की परवरिश शाही हरम में हो। दुर्गादास राठौर और उनके समूह ने मुगल सम्राट के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अजीत सिंह और रानियों को दिल्ली से छुड़ाने का फैसला किया।

मुगल और दुर्गादास गुट में हाथापाई हुई। इसमें काफी नुकसान हुआ। अंतत: मुगल सल्तनत ने हार मान ली और अजीत सिंह को वापस देने का फैसला ले किया। अजीत सिंह और उनकी मां को मारवाड़ अबू सिरोही के पास अरावली पहाड़ियों में सुरक्षित रखा गया। यहीं वो पले बढ़े।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों ने मेवाड़ पर पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की। ऐसे में दुर्गादास ने राठौड़ और सिसोदिया समेत कई समुदायों के साथ मिलकर छापामार रणनीति के साथ मुगलों से लोहा लिया। मारवाड़ की जंग में लड़ने के लिए औरंगजेब ने अपने बेटे सुल्तान मुहम्मद अकबर को भेजा, जिसे दुर्गादास ने अपनी ओर मिल लिया। दोनों गुटों के बीच करीब 30 साल तक जंग चली।

1704 में मुहम्मद अकबर की मौत हो गई। तब औरंगजेब ने दुर्गादास से बात करके अपने पोते-पोती को मांगा। दुर्गादास ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। हालांकि दोनों के बीच लम्बे समय तक सम्बंध तनावपूर्ण बने रहे।

1707 में औरंगजेब की मौत के बाद, दुर्गादास ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने वाली वाली मुगल सेना को बेदखल कर दिया। अजीत सिंह अंतत: जोधपुर के शासक बने। 22 नवंबर, 1718 को उज्जैन में शिप्रा पर 81 साल की उम्र में दुर्गादास की मृत्यु हो गई।

अमेरिका को भी भारत की जरूरत

मारूफ रजा

डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भारत का दौरा कर चुके हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे में संभावना है कि अपने दूसरे कार्यकाल में भी वह भारत का दौरा करें। अगर वह दूसरी बार भारत की यात्रा पर आते हैं, तो दो बार दौरा करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। इस लिहाज से उनकी यह यात्रा वाशिंगटन द्वारा भारत की विकास यात्रा को स्वीकृति होगी।

अमेरिका संभवत: भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 160 अरब डॉलर को पार कर गया है और इसके और बढ़ने की संभावना है। लेकिन अमेरिकी व्यापारिक टीम को परस्पर आदान-प्रदान समझौते पर अड़ना नहीं चाहिए, जिसके तहत अमेरिका जोर दे रहा है कि 2000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय वाला भारत 60,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय वाले अमेरिका के साथ बराबरी से व्यापार करे। हालांकि, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उनकी टीम द्वारा अमेरिकी चिंताओं को दूर करने के हर संभव प्रयास के बावजूद अतीत में ट्रंप का दृष्टिकोण समझौते को टालने का रहा है। अगर उन्होंने व्यापार समझौता किया होता, तो आज भारत अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते करके विशाल एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते का हिस्सा बन सकता था।

बढ़ती अमेरिकी मांगों को पूरा किए जाने के बावजूद व्यापार मुद्दों पर अमेरिका की इसी हठधर्मिता के कारण भारत ने अब अपनी सीमाएं तय कर दी हैं, जिसका मतलब है कि अब अमेरिका को लगभग दस अरब डॉलर मिल भी सकते हैं और नहीं भी। इससे अमेरिका से भारत की रक्षा खरीद करीब 25 अरब डॉलर हो जाएगी, क्योंकि पांच वर्षों से ज्यादा समय से अमेरिका भारत का शीर्ष सैन्य आपूर्तिकर्ता रहा है। फिर भी अमेरिकी रक्षा कंपनियां, जिनके पास

बड़ा बजट और उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, भारत से और अधिक रक्षा अनुबंध चाहती हैं। हाल ही में भारत ने रूसी सैन्य हार्डवेयर खरीदा है। मास्को ने खुशी-खुशी भारत को अकुला परमाणु हमला पनडुब्बियां और पांच भारतीय शहरों के लिए शीर्ष स्तर की ट्रायंफ मिसाइल कवच की आपूर्ति की है। इन सभी खरीद के लिए भारत को अमेरिका के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) शुरू करने की जरूरत है, जिसमें भारत में 'ड्रोन' और ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन शामिल है, क्योंकि पूर्व की दो घटनाओं-ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या और दूसरा सऊदी तेल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले-ने अब भविष्य के लिए ड्रोन को सबसे सस्ता और अधिक प्रभावी हथियार बना दिया है। इस्राइल-ईरान-हिजबुल्ला-फलस्तीन संघर्ष में जिस तरह से ड्रोन एक प्रमुख हथियार बनकर उभरा है, उससे भी इसके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। भविष्य में पूरी दुनिया में होने वाले संघर्षों में ड्रोन की भूमिका भी बढ़नी तय ही है।

सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ऐसी तकनीक भारत को हस्तांतरित करने के लिए सहमत होगा, जिससे पाकिस्तान में और अधिक चिंता पैदा हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़े लंबित रक्षा सौदों में से एक लड़ाकू विमानों का सौदा है, जिन्हें अमेरिका चाहता है कि भारत खरीदे, लेकिन कीमत और भारत द्वारा खरीदे जाने वाले 114 जेट के प्रकार को लेकर अनुबंध में देरी हो रही है। हालांकि, हथियारों और असैन्य परमाणु संबंधों के अलावा (जिसका सौदा उच्च बीमा प्रीमियम की मांग के कारण नहीं हुआ), भारत 6/7 जी प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिकी सहायता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भारत के बाजारों में प्रवेश करने के लिए 5जी की लड़ाई चीनी और जापानी कंपनियों के बीच चल रही है।

एक दूसरा क्षेत्र, जिसमें अमेरिका भारत की सहायता कर सकता है, वह है अंतरिक्ष में भारत के काम को आगे बढ़ाने की परियोजनाएं, जहां हम अब भी अमेरिका से बहुत पीछे हैं और मंगल ग्रह पर यान उतारने के हालिया प्रयास से यह बात सामने आई है।

संक्षेप में, भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों से रणनीतिक लाभ की तलाश कर रहा है, जबकि वाशिंगटन भारत के बाजारों में प्रवेश करने का इच्छुक है। हालांकि अमेरिकियों को अब भी यह समझना बाकी है कि भारत के डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के विशाल भंडार को (जो शायद दुनिया में सबसे बड़ा है) संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वे बहुत से किसानों को आजीविका प्रदान करते हैं। नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश मामलों की टीम के प्रमुख सदस्य भारत और उसकी सुरक्षा चिंताओं के बारे में जानते हैं-विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बारे में। हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) माइकल वाल्ट्ज एक सम्मानित सैन्य अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से दोतरफा पर खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका-भारत 'गठबंधन' के पक्ष में तर्क दिया है।

केवल दो महीने पहले वाल्ट्ज ने कहा था कि अमेरिका-भारत साझेदारी यह निर्धारित करेगी कि यह रोशनी की सदी होगी या अंधकार की सदी! इसके अलावा नवनियुक्त विदेश मंत्री मैक्रो रुबियो ने भी भारत के पक्ष में इसी तरह की?भावनाएं प्रकट की हैं, खासकर अमेरिका की उस नीति के लिए, जो भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरों से लड़ने में सहायता करे, भले ही रूसी सैन्य उपकरण खरीदने की सीमित छूट हो। यह भारत के लिए मधुर संगीत की तरह होगा, हालांकि यह सब आसानी से नहीं हुआ है। न केवल कई भारतीय राजनयिकों ने लगातार भारत के पक्ष में भावना का निर्माण किया है, बल्कि उनके प्रतिस्थापन ने भी अमेरिकी नीति निर्माताओं को खुश होने का अवसर दिया है। लेकिन सिर्फ सैन्य गतिरोध को टालना नहीं है, बल्कि व्यापार संबंधों को बढ़ाना भी राजनयिकों के लिए कठिन काम है। अब यह तो समय ही बताएगा कि सरकार, अमेरिका से महत्वपूर्ण समझौते करने और जरूरी सौदे हासिल करने में कितनी कामयाब रहती है।

आज का इतिहास

1933 फुज़ियान पीपुल्स सरकार चीन के फुज़ियान शहर में घोषित की गई।
1955 कर्नल टॉम पार्कर एल्विस प्रेस्ली ने आरसीए रिकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किये।
1963 संयुक्त राज्य अमेरिका के वायु सेना के पहले बी -2 स्टील्थ बॉम्बर को पहली बार कैलिफोर्निया के पामडेल में वायु सेना संयंत्र 42 में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया था।
1967 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने फ़िलिस्तीन के बारे में प्रस्ताव 242 पारित किया।
1967 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से इजरायल और मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के बीच छह-दिवसीय युद्ध के बाद संकल्प 242 को अपनाया।
1975 जुआन कालोर्स स्पेन के राजा बने।
1975 फ्रांसिस्को फ्रेंको की मृत्यु के दो दिन बाद, जुआन कार्लोस द्व को फ्रेंको द्वारा प्रख्यापित उत्तराधिकार के कानून के अनुसार स्पेन का राजा घोषित किया गया था।
1977 ब्रिटिश एयरवेज ने नियमित रूप से लंदन से न्यूयॉर्क शहर सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड सेवा का उद्घाटन किया।
1986 माइक टायसन ने लास वेगास में ट्रेवर बरबिक को हराकर अपना पहला मुक्केबाजी खिताब जीता।
1988 एंजेला मर्केल ने पहली महिला चांसलर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
1995 टॉय स्टोरी, केवल कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी का उपयोग करके बनाई गई पहली फीचर फिल्म थी।
1997 डायना हेडन ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता।
2005 केन्या में मतदाताओं ने विनाशकारी रूप से एक नया संविधान बनाया, जिसने राष्ट्रपति को अधिक शक्ति दी।
2005 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की असेंबली तब शुरू हुई जब Zarya, इसका पहला मॉड्यूल, बैजोनूर कोस्मोड्रोम, कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था।
2005 जर्मनी की सीडीयू पार्टी की एंजेला मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनीं।
2006 7 विदेशी तेल श्रमिकों को नाइजीरिया में बंधक बना लिया गया है। लोगों को बचाने के प्रयास में, एक बंधक, एक सैनिक और दो अपहरणकर्ताओं सहित 4 लोग मारे गए।
2007 तमिलों के पुनर्वास संगठन के चैरिटी पर श्रीलंका द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि यह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईमम को फंड कर रहा है

सीएम और गर्वनर की सियासी जंग का पुराना रहा है इतिहास

सत्येंद्र प्रताप सिंह

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी ने राहत की सांस ली थी। हालांकि, सीवी आनंद बोस का पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनकर आना, मानों सिर मुंडाते ओला पड़ना साबित हुआ। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता सरकार में शुरू से जंग लगातार जारी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर एक बार आमने-सामने हैं।

दरअसल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपित सिविक पुलिस वॉलंटियर संजय राय ने घटना के समय कोलकाता पुलिस के आयुक्त रहे विनीत गोयल और कोलकाता पुलिस के खुफिया विभाग के विशेष उपायुक्त पर साजिश करके उसे फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। राज्य सरकार पर भी आरोप लगाया है कि उनका (विनीत गोयल) ने समर्थन किया है। इन आरोपों के बाद राज्यपाल ने इस मामले में मुख्यमंत्री से विस्तृत रिपोर्ट तत्काल तलब किया है। दूसरी तरफ विधानसभाध्यक्ष बिमान बनर्जी दो टूक कहते हैं कि यह राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। राज्यपाल को अपने अधिकार क्षेत्र को समझना चाहिए।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य छिड़ी यह जंग कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी के शासनकाल में राज्यपालों केशरी नाथ त्रिपाठी, जगदीप धनखड़ और सीवी आनंद बोस से टकराव राज्य राजनीति के लिए कोई अजूबा घटना भी नहीं है। यह जरूर है कि इतने निम्न स्तर पर इसके पहले नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के चरित्र पर उंगली उठाये और राज्यपाल मानहानि के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाये। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री का वकील कहे कि जो कही हैं वह सही है और उस पर वह अडिग हैं। वैसे पूरे देश में यह पहली घटना थी कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

ममता बनर्जी बनाम सीवी आनंद बोस का यह टकराव बताने को काफी है कि उनकी सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद कहां तक पहुंच चुका है। वैसे, राज्यपाल हों या फिर केंद्र सरकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु विरोध किया करते थे, उसी राह पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चल रही हैं। राज्य के लिए इसे विडंबना ही कहेंगे कि पिछले 57 वर्षों में जितनी भी पार्टियों की सरकारें बनी, उसमें कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी सत्तासीन दलों का राज्यपालों के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। इस पर एक नजर सिलसिलेवार डालते हैं।

धर्मवीर बनाम अजय मुखर्जी- राज्य के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो राज्यपाल के साथ सूबे की सरकारों के टकराव की कहानी पहली बार नवंबर 67 में शुरू हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल धर्मवीर ने मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया था। सभी गैर-कांग्रेसी दलों ने धर्मवीर की तीखी आलोचना की थी। वर्ष 1969 में फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन राज्यपाल के साथ विवाद नहीं थमा। हालात यहां तक पहुंच गए कि राज्य सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से धर्मवीर को पद से हटाने की मांग की जिसे मान लिया गया।

शांतिस्वरूप धवन बनाम ज्योति बसु-शांतिस्वरूप धवन को नए राज्यपाल के रूप में भेजा गया। उसके बाद ऐसा लगा कि अब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव नहीं होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। वर्ष 1971 में

राज्यपाल धवन के साथ एक बार फिर वामपंथियों का विवाद शुरू हो गया। इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में वामदलों ने 113 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए। कांग्रेस को 105 सीटें मिली। लेकिन राज्यपाल धवन ने कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। इस पर ज्योति बसु ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा था कि धवन के लिए 113 नहीं, 105 बड़ी संख्या है। राज्यपाल धवन का काफी विरोध हुआ था।

भैरव दत्त पांडे और अनंत प्रसाद शर्मा-समस्या की शुरुआत तब हुई जब 1980 में दिल्ली की गद्दी पर फिर से इंदिरा गांधी सत्तासीन हुईं। इसके बाद इंदिरा गांधी ने बीडी पांडे यानी भैरव दत्त पांडे को राज्यपाल बनाकर भेजा। माकपा के तत्कालीन कद्दावर राज्य सचिव प्रमोद दासगुप्ता ने कहा था कि बीडी का अर्थ भैरवदत्त नहीं, बल्कि 'बंग दमन' है। राज्यपाल के साथ तत्कालीन वाम सरकार का टकराव इतना बढ़ गया था कि तमाम वामपंथी बीडी पांडे को बंग दमन पांडे के नाम से पुकारते थे। वर्ष 1984 में बंगाल के राज्यपाल अनंत प्रसाद शर्मा बने। वाम सरकार का एपी शर्मा के साथ भी बहुत विवाद हुआ।

टीवी राजेश्वर और गोपालकृष्ण गांधी- दरअसल, वामपंथियों ने राज्यपाल का विरोध करना अपना स्वभाव बना लिया था। कॉमरेड यहां तक कहने लगे थे कि राज्यपाल का पद ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसलिए जब भी कोई राज्यपाल बनकर आता तो उसके खिलाफ वामपंथी मुखर हो जाते। इसका एक बड़ा उदाहरण टीवी राजेश्वर हैं। देश के पूर्व खुफिया प्रमुख टीवी राजेश्वर 1990 में बंगाल के राज्यपाल बने।

वामपंथी नेता कहने लगे कि जासूस को भेजा गया है, ताकि राज्य सरकार की जासूसी कराई जा सके। वाम सरकार का अगला टकराव तत्कालीन राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी के साथ हुआ था। गोपालकृष्ण गांधी, नंदीग्राम की घटना को लेकर वाम सरकार के खिलाफ मुखर हुए थे। मार्च%07 में नंदीग्राम में हुई गोलीबारी को गोपालकृष्ण गांधी ने 'बोन चिलिंग टेरर' (हड्डी कंपा देने वाला आतंक) करार दिया था। इस पर राज्य में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। वाममोर्चा सरकार राज्यपाल के खिलाफ काफी मुखर हो गया था।

एमके नारायणन और केशरी नाथ त्रिपाठी- राज्यपाल एमके नारायणन ने वर्ष 2011 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ऐसा लगा कि अब सब सही होगा पर स्थिति नहीं बदली। राज्यपाल नारायणन से टकराव के बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बने केशरी नाथ त्रिपाठी ने सूबे में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुंह खोला तो संवाददाता सम्मेलन बुलाकर ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल ने उनका अपमान किया है। 27 जुलाई 19 को बिदाई के पहले राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टिकरण नीति राज्य के सामाजिक सौहार्द्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। मुख्यमंत्री को प्रत्येक नागरिक से बिना किसी भेदभाव के समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए।

मेरा मानना है कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार की जरुरत है। जो चीज मुझे पसंद नहीं थी वह थी निचले स्तर पर पुलिस का हस्तक्षेप। उच्च पुलिस अधिकारी अच्छे हैं। वे ईमानदार हैं, लेकिन कांस्टेबल और उपनिरीक्षक स्वयं का किसी न किसी पार्टी से जुड़ाव इस सीमा तक रखते हैं कि वे चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बरकरार नहीं रख पाये।

जगदीप धनखड़ बनाम ममता बनर्जी-राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मध्य तनातनी तो प्राय: रोज की बात थी। कोरोनाकाल में स्थिति बद से बदतर तब हुई जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ के दिए बयान और उनके द्वारा लिखे दो पत्रों से नाराज ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ पर सत्ता हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया।

ममता बनर्जी ने 14 पेजों के पत्र में लिखा- मैं आपसे विनती करती हूं कि संकट की इस घड़ी में सत्ता हड़पने की अपनी कोशिशें तेज करने से आप बाज आ जाइए।आपको अपने ट्वीट में आधिकारिक पत्रों और लोगो का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए।

ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर उपदेश देने और संवैधानिक नियमों का खुद पालन किये बगैर उसका प्रवचन देने तथा उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, राज्यपाल मेरी नीतियों से सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य है कि उनके पास केवल इसका संज्ञान लेने के सिवाय कोई अधिकार नहीं है। जब तक सरकार के पास बहुमत है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर कोरोना संक्रमितों और मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी को आंकड़े छिपाने की बजाय राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त करने का काम करना चाहिए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्यपाल धनखड़ ने पश्चिम बंगाल में खराब स्थिति की बात कही थी।

विचारों की लड़ाई हैं चुनाव तार्किक ढंग से लड़ें?

विश्वनाथ सचदेव

धर्म वैयक्तिक आस्था की चीज है। उसका चुनावी-लाभ उठाने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। विविधता में एकता वाला देश है हमारा। धार्मिक विविधता हमारी ताकत है, इसलिए धर्म को राजनीति का हथियार बनाना अपने संविधान की भावना के विरुद्ध काम करना है। यह अपने आप में एक अपराध है। इस अपराध की 'सजा' मतदाता ही दे सकता है। ऐसा कब होगा या हो पाएगा, पता नहीं। लेकिन होना चाहिए। जागरूक और विवेकशील मतदाता का दायित्व बनता है कि वह गलत तरीके से (पढ़िए आपराधिक तरीके से), की जाने वाली राजनीति को नकारे। बात सिर्फ सांप्रदायिक भावना को उभारने की ही नहीं है। चुनाव-प्रचार जिस तरह से घटिया होता जा रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। जनतंत्र में चुनाव विचारों की लड़ाई होता है। अपने विचार के समर्थन में तार्किक तरीके से प्रचार करने का सबको अधिकार है। लेकिन अधिकार का यह कैसा उपयोग है कि हम सहज शालीनता को भी भूल जाएं? हम अपनी स्वतंत्रता के 'अमृत-काल' में हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री ने क्या सोचकर यह नाम रख दिया था, पर इसका अभिप्राय यही लगता है कि हम बताना चाहते हैं कि हमारा जनतंत्र परिपक्व हो चुका है। इस परिपक्वता का तकाजा है कि हम छिछली राजनीति से स्वयं को बचाएं। विचारों की लड़ाई ठोस तर्कों से लड़ी जाती है, बेहूदा नारों से नहीं। चुनाव का अवसर राजनेताओं के लिए अपनी क्षमता को उजागर करने का होता है। यह दिखाने का अवसर होता है कि हम प्रतिपक्षी से बेहतर कैसे हैं। यह दावा करना पर्याप्त नहीं है कि मैं दूसरे से बेहतर हूं, बेहतरी को अपने व्यवहार से सिद्ध भी करना होता है। दुर्भाग्य ही है कि हमारे नेता, चाहे वे किसी भी रंग के क्यों न हों, न इस बात को समझते हैं और न ही समझना चाहते हैं। चुनाव-प्रचार के दौरान जिस तरह भाषा और नारेबाजी लगातार घटिया होती हम देख रहे हैं वह हमारी जनतांत्रिक समझ पर सवालिया निशान ही लगाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि पहले हमारी राजनीति का स्तर बहुत अच्छा था, पर इतना घटिया निश्चित रूप से नहीं था। धर्म के आधार पर राजनीति पहले भी होती थी, पर वैसी नहीं जैसी अब हो रही है। भगवे या हरे या नीले या सफेद रंग ने हमारी राजनीति को बदरंग बना दिया है। नेता यह बात नहीं समझना चाहते, पर मतदाता को इसे समझना होगा-दांव पर उसका भविष्य लगा है!

बद से बदतर होती जा रही है चुनावी बयानबाजी

विपिन पब्बी

महाराष्ट्र और झारखंड में उम्मीदवारों की किस्मत तय होने के साथ ही, एक कटु और बेबाक प्रचार अभियान का अंत हो गया है। दोनों राज्यों में चुनावों का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, यह प्रचार अभियान इतिहास में अब तक के सबसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी अभियानों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। मुझे याद है कि मैंने पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के समाप्त होने के ठीक बाद भी ऐसा कहा था। दुर्भाग्य से, खासकर सांप्रदायिक रंग के साथ राजनीतिक बयानबाजी का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है और अभी-अभी सम्पन्न हुए चुनाव अभियान को अब सबसे ज्यादा सांप्रदायिक कहा जा सकता है।

दोनों राज्यों, खासकर महाराष्ट्र में हुए चुनावों में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों तथा कांग्रेस एवं उसके गठबंधन सहयोगियों दोनों के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा था। हरियाणा चुनावों के आश्चर्यजनक परिणाम, जिसमें भाजपा ने सभी को गलत साबित कर दिया और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले अभियान को बढ़ावा

दिया। हालांकि, जाहिर है कि भाजपा देश के सबसे समृद्ध और दूसरे सबसे बड़े राज्य को जीतने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। कांग्रेस और अन्य गठबंधन दलों को अतीत में नरेंद्र मोदी के लिए 'मौत का सौदागर' जैसे नारे लगाने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सांप्रदायिक बयानों और नारों से मीलों आगे हैं।

उनके नारे जैसे 'बंटेंगे तो कटेंगे' और 'एक हैं तो सेफ हैं' में स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक रंग है जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। अधिक बच्चे पैदा करने वाले या जिनके सदस्य 'घुसपैठिया' हैं और जो मंगलसूत्र, जमीन और सोना छीन लेंगे, उनका संदर्भ स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक रंग देता है।

इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान, मोदी ने दावा किया था कि विपक्ष को मिलने वाला हर वोट हिंदुओं द्वारा अर्जित धन का उपयोग उन मुसलमानों को वितरित करने के लिए किया जाएगा जिनके अधिक बच्चे हैं और जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को हिंदू महिलाओं के 'मंगलसूत्र' भी वितरित कर सकती है। सांप्रदायिक पहलू को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में 'घुसपैठियों' को दीमक बताते रहे हैं और आदिवासियों से कहते रहे हैं कि वे अपनी मासूम बेटियों को अपनी तीसरी या चौथी पत्नी बना लेंगे।

विडंबना यह है कि पार्टी के नेता जाति जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की आलोचना करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि यह 'विभाजनकारी' है और इससे सामाजिक तनाव पैदा होगा। सबसे मुखर और सबसे सांप्रदायिक नेताओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा शामिल हैं। वे कभी भी विकास या प्रगति या यहां तक कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम समुदाय है और वे हर बार चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलते समय और भी गहराई में उतर जाते हैं। दुर्भाग्य से न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही भारत के चुनाव आयोग ने इस ज्वार को रोकने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने चुनावों के इस तरह के सांप्रदायिकरण पर आंखें मूंद ली हैं या कान बंद कर लिए हैं।

हाल ही में चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया सांप्रदायिक रंगत को रोकने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दलों से विकलांग लोगों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कहा, जिसमें राजनीतिक विमर्श में गूंगा, बहरा, लंगड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करना शामिल है। यह एक अच्छा और उचित निर्देश था, लेकिन यह उन राजनेताओं को बाहर निकालने से क्यों कतरा रहा है जो स्थिति को सांप्रदायिक बनाने और समाज को विभाजित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। दोनों राज्यों में सबसे लोकप्रिय पार्टी या गठबंधन को चुनाव जीतने दें, लेकिन राजनीतिक नेताओं को देश के सर्वोत्तम हित में नई गहराई में जाने से बचना चाहिए।

एलन मस्क ढिंढोरा पीट रहे, पीएम मोदी ने चुपचाप किया?

हरीश गुप्ता

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की राह पर चल रहे हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी सरकार के आकार में कटौती करने का काम सौंपा है? बिल्कुल नहीं। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी केंद्र सरकार के आकार को छोटा करने और फिजूलखर्ची में कटौती करने के लिए उत्सुक रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक सरकार में रिक्त पदों को नहीं भरा और नौकरशाही को अनुशासित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए, जिससे सही संकेत गए। ऐसा नहीं है कि उनके पूर्ववर्तियों ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2012 में केंद्र सरकार ने संगठित कार्यबल के 8।5ब को रोजगार दिया, जो 1994 के 12।4ब से कम था। निश्चित रूप से, मोदी के शासन में यह आंकड़ा काफी कम हुआ है। संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार, 1 जुलाई 2023 तक, केंद्र सरकार के 48।67 लाख कार्यरत कर्मचारी और 67।95 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी थे।

मोदी ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने के दबाव के आगे भी घुटने नहीं टेके, हालांकि कुछ भाजपा शासित राज्य सरकारों ने राजनीतिक मजबूरियों के चलते ओपीएस को वापस लागू कर दिया।

मोदी सार्वजनिक रूप से यह दावा नहीं कर सकते कि वे सरकार का आकार छोटा कर देंगे, जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है।

भारत में यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है और बढ़ती बेरोजगारी का किसी भी सरकार की स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है। मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद दो प्रमुख सहयोगियों पर निर्भर है और कठोर निर्णय चुपचाप ले रही है।

उन्होंने तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में 'बाबुओं' को प्रशिक्षित करने के लिए नौकरशाही में अपने 'कर्मयोगी' विजन को लागू करने के लिए 2021 में इंफोसिस के पूर्व सीईओ एसडी शिबू लाल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। वे बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र से अनुबंध के आधार पर प्रतिभाओं को लाने की प्रणाली को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, हालांकि यह सफल नहीं रहा है। कारण! नौकरशाही इस मजबूती से सिस्टम में समाई है कि बाहरी व्यक्ति के लिए टिक पाना मुश्किल है।

सार्वजनिक उपक्रमों को लाभदायक उपक्रमों में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी की योजना 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद सफल हुई है। 2021 में सार्वजनिक उद्यम

चयन बोर्ड (पीईएसबी) का नेतृत्व करने वाली पहली निजी क्षेत्र की विशेषज्ञ मल्लिका श्रीनिवासन की नियुक्ति ने एक नए युग का संकेत दिया।

श्रीनिवासन निजी क्षेत्र की कंपनी ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट (टैफे) लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थीं। पीईएसबी में उनके नेतृत्व ने प्रमुख प्रबंधकीय पदों के लिए चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी उनके काम से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु सीमा से आगे नवंबर 2025 तक एक और साल के लिए बढ़ा दिया।

नियमों में संशोधन किया। पीईएसबी का काम केंद्र सरकार के तहत 300 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों में प्रमुख नियुक्तियां करना है और उनमें से अधिकांश भारी घाटे में चल रहे थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भले ही मोदी सरकार पर अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया हो।

लेकिन मोदी ने उनमें से अधिकांश को लाभ कमाने वाली कंपनियों में बदल दिया है, न कि उन्हें पहले की तरह सस्ते में बेचा है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर अपने पूर्ववर्तियों द्वारा बनाए गए 23 सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने का भी आरोप लगाया, जिसमें एयर इंडिया का सबसे बड़ा निजीकरण भी शामिल है, जो दो दशकों से घाटे में चल रहा था।

शेयरों को किस्तों में भारी कीमत पर बेचने और लाभांश अर्जित करने से सरकार की झोली में पैसा आया है। यह अलग बात है कि चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार 2023-24 में अपने विनिवेश कार्यक्रम को पूरा करने में असमर्थ रही। ऐसी खबरें हैं कि नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की आठ प्रमुख उर्वरक कंपनियों को क्रमिक तरीके से बेचने की सिफारिश की थी।

लेकिन सरकार ने इसमें देरी की क्योंकि वह घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ बंद संयंत्रों को फिर से खोल रही है। सरकार का लक्ष्य आयातित उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम करना और संयंत्रों को बेचने से पहले उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उम्मीद है कि यूरिया आयात में उम्मीद से पहले ही 30 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी। उर्वरक सब्सिडी को पहले ही वित्त वर्ष 2024 में 1,88,894 करोड़ रुपए से घटाकर वित्त वर्ष 2025 में 1,64,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मोदी सरकार ने खर्च कम करने के लिए एक और तरीका अपनाया है। उसने एक नौकरशाह या नेता को न सिर्फ दोहरा प्रभार बल्कि चार-चार विभाग, कंपनियां या मंत्रालय देने शुरू कर दिए हैं। वह लंबे समय से बड़ी संख्या में कंपनियों को बिना प्रमुख के रख रही है और दूसरे विभाग का प्रभार किसी और विभाग के प्रभारी नौकरशाह को दे रही है।

खबरों की मानें तो तीन दर्जन से ज्यादा नौकरशाह दोहरे या तिहरे प्रभार संभाल रहे हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। ताजा मामला भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का है, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मानकों को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण निकाय है।

गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी और पूर्व वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया के नवंबर 2021 में सेवानिवृत्त होने के बाद से अध्यक्ष का पद तीन साल से खाली पड़ा है। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। सरकार में इस बात को लेकर घोर असमंजस की स्थिति है कि एफएसएसएआई का अध्यक्ष किसे बनाया जाए, किसी नौकरशाह को या वैज्ञानिक को। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के नाम की सिफारिश की गई थी, लेकिन शीर्ष अधिकारी चाहते थे कि एफएसएसएआई का नेतृत्व कोई वैज्ञानिक या इस क्षेत्र का विशेषज्ञ करे।

एक वैज्ञानिक के नाम की भी सिफारिश की गई थी और एसीसी से उम्मीद थी कि वह इसे मंजूरी दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुश्री श्रीवास्तव से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एफएसएसएआई का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। एक अन्य स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा भी एफएसएसएआई के प्रमुख थे।

भाजपाई हुए कैलाश गहलोत, केजरीवाल के लिए बहुमत पाना होगा मुश्किल

संतोष पाठक

रविवार को दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले कैलाश गहलोत ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। हालांकि गहलोत के आतिशी मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही यह तय माना जा रहा था कि उनका अगला ठिकाना भाजपा ही होने जा रहा है।

इसी के साथ अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि कैलाश गहलोत कुछ महीनों बाद ही दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या कैलाश गहलोत का कद वाकई इतना बड़ा है कि %शीशमहल% सहित उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों से अरविंद केजरीवाल की छवि को कुछ नुकसान पहुंच सकता है।

यह बात बिल्कुल सही है कि कैलाश गहलोत आज जो आरोप लगा रहे हैं,लगभग उसी तरह के आरोप भाजपा पिछले लंबे समय से लगा रही है। दूसरी बात यह है कि , यह सब जानते हैं और मानते भी हैं कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी वन मैन पार्टी बन कर रह गई है। आप का मतलब, आज की तारीख में सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही रह गया है। ऐसे में बाकी मुद्दे लगभग गौण हो जाते हैं।

अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सबसे बड़ी ताकत वो लाभार्थी वर्ग है जो उन्होंने महिलाओं को फ्री डीटीसी बस सेवा और दिल्लीवासियों को फ्री बिजली और पानी देकर तैयार किया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों के साथ-साथ जाट और मुस्लिम समुदाय के सॉलिड वोट बैंक का इतना मजबूत किला बना रखा है कि जिसे ढहाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।

यही वजह है कि भाजपा इस बार अरविंद केजरीवाल के मजबूत मोहरों के सहारे ही उन्हें विधानसभा चुनाव में मात देना चाहती है। कैलाश गहलोत का भाजपा में आना तो महज एक शुरुआत माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल के कई कद्दावर नेता भाजपा का

दामन थाम सकते हैं। ये सभी नेता आप सरकार की विफलताओं के साथ- साथ केजरीवाल की छवि पर भी चोट करेंगे।

कैलाश गहलोत को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा ने दिल्ली के जाट समुदाय को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में भाजपा , आप में और ज्यादा तोड़-फोड़ कर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले दिल्ली के मतदाताओं को भी लुभाने का प्रयास करेगी।

अगर वाकई भाजपा, अपनी रणनीति में कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसका असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा। आप के लिए इस बार बड़ी चुनौती सिर्फ भाजपा की तरफ से ही नहीं आ रही है बल्कि कांग्रेस खासकर राहुल गांधी भी इस बार दिल्ली में पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश ईकाई प्रदेश में %दिल्ली न्याय यात्रा% निकाल रही है। यह माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूती से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो फिर मामला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो जाएगा। शीशमहल को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों अरविंद केजरीवाल की छवि पर लगातार चोट कर रहे हैं। ऐसे माहौल में यह तय माना जा रहा है कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए इस बार बहुमत तक पहुंचना काफी मुश्किल होने जा रहा है। हम सबको दिल्ली में 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भाजपा को 32 (सहयोगी के साथ), आप को 28 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

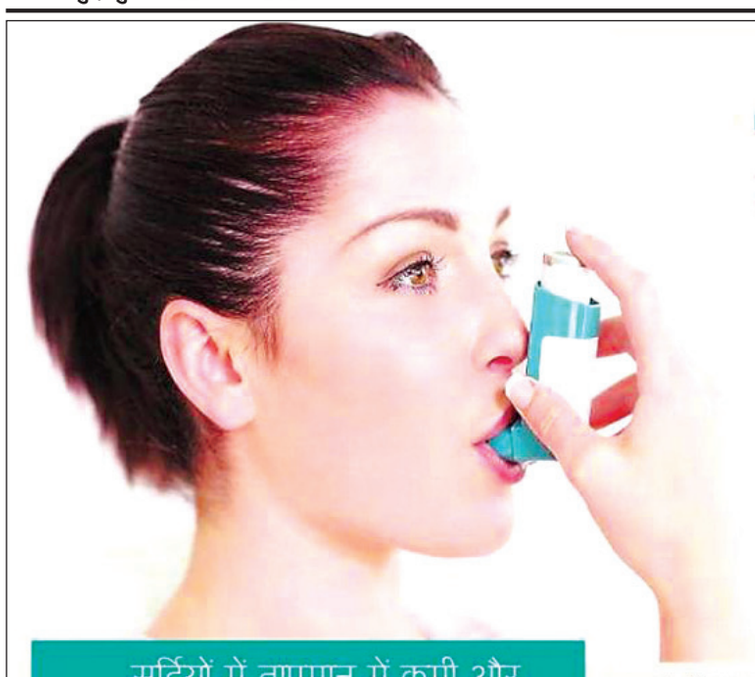

सर्दियों में सांस के रोगी रहें सचेत

सर्दियों में तापमान में कमी और वातावरण में प्रदूषित तत्वों की बढ़ी हुई मात्रा सेहत के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। सर्दियों का मौसम खासतौर पर सांस के मरीजों के स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन जाता है। इस मौसम में सांस संबंधी दिक्कतें जैसे दमा, फ्लू और सर्दी-जुकाम के मरीजों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

प्रदूषित कोहरे का दुष्प्रभाव

सर्दियों में होने वाला कोहरा (जो वायुमंडल की जलवाष्प के संघनित होने से बनता है) कमोबेश हानिरहित होता है, लेकिन धुएं और सस्पेन्डिड पार्टिकल्स (छोटे-छोटे प्रदूषित कणों) के इर्द-गिर्द जमने से बना स्मोग (प्रदूषित कोहरा) मानव शरीर और खासतौर पर श्वसन तंत्र के लिए किसी विपत्ति से कम नहीं होता। इस वजह से लोगों की आंखों में जलन, आंसू, नाक में खुजली, गले में खराश और खांसी जैसे लक्षण सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही सांस की नली की संवेदनशीलता तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है, जिससे सांस की नली सिकुड़ती है। इस कारण सांस के रोगियों में समस्या की आशंका बढ़ जाती है।

वृद्ध रहें सजग

वृद्धों में सांस संबंधी समस्याएं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। दरअसल बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण उन्हें सांस संबंधी बीमारियों का ज्यादा खतरा रहता है।

दमा या अस्थमा- वातावरण में किसी भी प्रकार के बदलाव से शरीर में परिवर्तन होता है, जिससे, एलर्जी और अस्थमा के रोगी मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। जाड़े में इन मरीजों की परेशानियां बढ़ जाती है। इसलिए उन्हें विशेष तौर पर अपना ख्याल रखने की सलाह दी जाती है।

फ्लू या इंफ्लूएंजा- यह समय फ्लू या इंफ्लूएंजा के वाइरस के सक्रिय होने का है। इस कारण फ्लू के मामलों में काफी वृद्धि हो जाती है। बच्चों, वृद्धों, गर्भवती महिलाएं और एच.आई.वी. से पीड़ित रोगियों में यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।

क्या करें

- सांस के रोगी खासकर दमा के मरीज न सिर्फ सर्दी से बचाव करें बल्कि नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहें। डॉक्टर की सलाह से अपने इनहेलर की डोज भी दुरुस्त कर लें। कई बार इनहेलर्स की मात्रा बढ़ानी होती है।
- सर्दी से बचकर रहें। पूरा शरीर ढकने वाले कपड़े पहनें। सिर, गले और कान को खासतौर पर ढकें।
- सर्दी के कारण साबुन-पानी से हाथ धोने की अच्छी आदत न छोड़ें।
- गुनगुने पानी से नहाएं।
- सर्दी के मौसम में मालिश लाभप्रद है।
- सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू और सांस की अन्य बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को सुबह- शाम भाप(स्टीम) लेनी चाहिए।
- फ्लू के रोगी खांसते या छींकते समय मुंह पर हाथ रखें या रूमाल का प्रयोग करें।
- फ्लू के रोगियों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं जैसे रूमाल व चादरों आदि को सुरक्षित विधि से साफ करें।
- अगर आप में फ्लू के लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और घर मे ही रहें।
- फ्लू पीड़ित से कम से कम 1 मीटर दूर रहें।
- हाथ मिलाने या गले मिलने से बचें, भारतीय पद्धति के अनुसार नमस्कार करें।

क्या न करें

- सर्दी में सांस के मरीजों को सुबह की सैर नहीं करनी चाहिए।
- सुबह ठंडे पानी से न नहाएं। सांस के रोगियों को अलाव के धुएं से बचना चाहिए, अन्यथा इससे उन्हें सांस का दौरा पड़ सकता है।

घर पर करें गोभी और मिर्च से रोगों का उपचार

जार्जटाऊन यूनिवर्सिटी मैडीकल सैंटर के शोधकर्ताओं के अनुसार फूलगोभी, पत्तागोभी तथा जलकुंभी परिवार की सब्जियों में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो मानव एवं जानवर दोनों में फेफड़े का कैंसर रोकने में सहायक होता है।

शोधकर्ताओं के अनुसार 'प्रेफेक्स' नामक एक ऐसा पदार्थ गोभी में पाया जाता है जो फेफड़े को कैंसरग्रस्त होने से रोकता है। यह पदार्थ सैक्स उत्तेजक भी होता है। इसी प्रकार मिर्च खाने से शरीर की चर्बी कट जाती है और वजन कम हो जाता है।

मिर्च की तासीर के कारण चर्बी बढ़ाने वाली कोशिकाएं खुद ब खुद नष्ट होने लगती है। ताईवान के शोधकर्ता चिन-लिन-शू के अनुसार मिर्च शरीर के चयापचय की प्रक्रिया को तेज करती है और यह मोटापे को कम करने के साथ ही कालरा तथा ब्रांकाइटिस जैसी बीमारियों का उपचार भी करती है।

गोभी और मिर्च से बहुत से रोगों का उपचार घर पर ही किया जा सकता है। आईए जानें कैसे

गोभी

1 गोभी में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को दरूस्त रखते हैं और पेट संबंधी रोगों से राहत देते हैं।
2 गोभी का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी का खतरा कम होता है।
3 गोभी का सेवन मोटापे से निजात दिलाता है।
4 गोभी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो शरीर की हड्डियों के लिए काफी फायदेमंद होती है और दांतों को भी मजबूत बनाने में मददगार साबित होती है।

मिर्च

1 जब आप हरी मिर्च अपने दांत से चबाते हैं तो इसका तीखा अनुभव आपके मुंह में अधिक थूक पैदा करता है जो रक्त के थक्कों को घोलने में काफी सहायक होता है।
2 हरी मिर्चों में विटामिन सी की मौजूदगी शरीर को खांसी, जुकाम तथा श्वास संबंधी अन्य समस्याओं से बचाने में सहायता करती है।
3 हरी मिर्च में मौजूद विटामिन के ओस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करता है।
4 हरी मिर्च एक प्राकृतिक दर्द निवारक है और यह ओस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियों में इलाज में काफी लाभदायक होती है।
5 मोटापे से पीड़ित लोगों में कोलैस्ट्रॉल के स्तरों को कम करने में हरी मिर्चें काफी सहायक होती हैं।

मानव पर रंगों का प्रभाव

सफेद रंग हल्केपन एवं शीतलता का आभास देता है।

पीला रंग उत्फुल्लता, हल्केपन खुलेपन और गर्माहट का आभास देता है, नब्ज की रफ्तार तेज करता है परंतु आक्रामक प्रतिक्रिया भी पैदा कर सकता है।

बैंगनी रंग थकान और भारीपन का भ्रम उत्पन्न कर थकान, बोरियत या बोझ की अनुभूति करता है।

गहरा नीला रंग मस्तिष्क को विश्रांति देता है किन्तु दुख का बोध भी कराता है। गहरे नीले रंग से पूरा कमरा ठंडा एवं भरा-भरा प्रतीत होता है।

हरा रंग शांति एवं शीतलता का अहसास कराता है। आंखों से दबाव घटाकर नेत्र ज्योति तेज करता है। खून का दबाव भी सामान्य करता है। हल्का नीला रंग शीतलता व अलगाव द्वारा चैन देता है। काला रंग ओजस्विता कम करता है, अवसादकारक एवं उत्पीड़क बोझ देने वाला है। काले रंग पुते तल काफी बड़े प्रतीत होते हैं। भूरा रंग स्थायित्व, गर्म और मानसिक संतुलन बोधकारक होता है। सलेटी रंग को ठंडा, नीरसता व विरक्तिबोधक माना जाता है। श्वेत एवं नीले रंग के सम्मिश्रण को शीतलता और चैन का द्योतक कहा गया है। जामुनी रंग गर्म एवं उत्साहवर्धक माना गया है। लाल रंग गर्मजोशी, मनोबल बढ़ाता है, मगर देर तक हावी रहना थकान एवं धड़कन बढ़ाता है

ठंड में त्वचा रोगों से बचाव के घरेलु नुस्खे

1 सर्दी के मौसम में स्वस्थ त्वचा के लिए जरूरी है नियमित स्नान। भले ही आप प्रतिदिन न नहाएं परंतु हर दूसरे दिन नहाने का नियम बनाएं। जिस दिन नहीं नहाएं, उस दिन स्पंज करें तथा अंदर के कपड़े अवश्य बदलें। नहाने के लिए ठंडा-गर्म जैसा पानी चाहें, इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 जाड़े में साबुन का प्रयोग ज्यादा न करें। नहाने से पहले पूरे बदन में तेल लगाएं। नहाने के बाद तेल या माश्चराइजर का उपयोग करें। पानी से करने वाले काम एक ही बार में निपटा लें। बार-बार पानी में हाथ न डालें। यदि पानी का काम करना जरूरी हो तो पहले हाथों में मलाई लगाएं। दस्ताने पहन कर काम करने से त्वचा सुरक्षित रहती है।
3 सर्दियों में धूप का नियमित सेवन करके विलब्लेंस व डर्माटाइटिस जैसे रोगों से बचा जा सकता है। धूप में उतना ही बैठें जितनी देर आराम महसूस करें। अगर त्वचा लाल पडने लगे या सूजने लगे, तो धूप से हट जाएं। जिन्हें धूप से एलर्जी है उनके लिए सर्दी की धूप भी नुक्सानदायक है। ऐसे लोग धूप में कम निकलें। जब भी धूप में निकलें तो सिर पर स्कार्फ बांध लें या छतरी भी लगा सकते हैं।
4 हाथ-पैर की उंगलियों के सुन्न होने, खून का दौरा कम होने या त्वचा के फटने से बचने का सबसे अच्छा उपाय है संतुलित आहार। भोजन में दूध, दही और हरी सब्जियां खूब लें। विटामिन ए ज्यादा से ज्यादा लें। त्वचा के लिए गाजर का सेवन बहुत फायदेमंद है।
5 यूरिया आयंटमैंट त्वचा के फटने, सूजन और लाल होने वाली त्वचा के उपचार के लिए बहुत उपयोगी है। यह यूरिया से बनती है। इसको मलने से त्वचा काफी देर तक मुलायम बनी रहती है। इसके नियमित इस्तेमाल से त्वचा में होने वाले रोगों से बचा जा सकता है तथा त्वचा स्वस्थ रहती है।

कहीं आप भी खून की कमी का शिकार तो नहीं हो रहे

आज के भागदौड़ भरे जीवन में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ रहा है। जिससे भोजन में पौष्टिक आहार की कमी के कारण आज प्रत्येक वर्ग के लोग खून की कमी से जूझ रहे हैं। जिसमें अधिकतर संख्या युवाओं की है जिसके कारण उन्हें कमजोरी आदि की शिकायतें होने लगी हैं। खून की पाई जाने वाली इस कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का प्रमुख कारण सही प्रकार की डाइट न लेना है। पुरुषों में खून की मात्रा 14 से 18 ग्राम प्रति डैसीलीटर होनी चाहिए। वहीं महिलाओं में यह 12 से 16 ग्राम प्रति डैसीलीटर है। इससे कम मात्रा में पाए जाने वाले खून को एनीमिया कहते हैं। वैसे 10 ग्राम से अधिक खून वाले भी स्वस्थ रहते हैं, परंतु इससे कम खून वाले को अधिक से अधिक डाइट लेनी चाहिए।

एनीमिया की 3 स्टेज होती हैं, जिनमें प्रथम स्टेज को माइलड कहते हैं, जो 10 से 12 ग्राम होती है। वहीं 6 से 10 ग्राम को मोडरेट व 6 ग्राम से कम की स्थिति खतरनाक होती है। जिसे सीवियर एनीमिया कहते हैं।

एनीमिया अत्यधिक गंभीर रोग तब होता है जब हैपिटाइटिस बी, सी तथा एच.आई.वी. जैसे संक्रमण होते हैं। डाक्टरों का सुझाव है कि अधिक मात्रा में भी आयरन का सेवन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

कैसे करें खून की कमी पूरी

1 एनीमिया से निजात पाने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन, मांस, मछली में ही नहीं दूध, हरी सब्जियां, मटर, फलियों तथा पतेदार सब्जियों, शीरा, गुड़, किशमिश, खजूर, सेब इन सबमें अलग-अलग रूप में मिल जाते हैं। इन तत्वों में खून बनने में सहायता मिलती है।

2 खाना खाने से पहले व बाद में आधे घंटे तक चाय का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चाय खाने में मिलने वाले पौष्टिक तत्वों को डाइजेस्ट नहीं होने देती।

3 आयरन युक्त डाइट तभी फायदेमंद होती है, जब उसके साथ विटामिन सी का भी सेवन किया जाए। विटामिन सी के लिए अमरूद, आंवला और संतरे का जूस लें। वैसे तो बैलेंस्ड डाइट और हैल्दी लाइफ स्टाइल ही काफी है लेकिन फिर भी किसी कारण से एनीमिया हो जाता है तो प्रापर ट्रीटमैंट लेना आवश्यक है। डाक्टर की सलाह से ब्लड टैस्ट कराएं ताकि बीमारी का कारण पता चल सके। उसके बाद ही डाक्टर आपका सही ट्रीटमैंट कर सकेंगे।

रूखी त्वचा को कोमल बनाता है नारियल तेल

ठंड के कारण कई समस्याएं होती हैं. इस मौसम में त्वचा के रोग और सर्दी-जुकाम होना आम बात है. इन समस्याओं से निबटने के लिए प्रस्तुत हैं कुछ आसान घरेलू उपाय, जिनसे इन समस्याओं से निबटा जा सकता है.

- रूखी त्वचा से बचने के लिए नैचुरल मॉस्च्यूराइजर, जैसे- नारियल तेल लगाएं.

- शहद के साथ गुलाब जल मिला कर चेहरे पर लगाएं. इससे त्वचा में चमक आयेगी और चेहरा साफ होगा.
- स्नान से पहले नारियल तेल लगा लें, इससे चिकनाई और कोमलता आयेगी.
- नीबू का रस लगाएं. इसमें मौजूद विटामिन-सी चेहरे की चमक बनाये रखती है.
- सर्दी के मौसम में विटामिन की कमी के कारण होठ फटने लगते हैं, इसलिए टमाटर, गाजर, साबूत अनाज और फल-सब्जियों का सेवन करें.
- नारंगी के छिलके के पाउडर में शहद मिला कर लगाने से त्वचा निखरती है.
- जितना हो सके, आहार में विटामिन-इ युक्त खाद्य पदार्थो, जैसे- पालक, बादाम, कद्दू आदि का सेवन करना बेहतर होता है.

सेहत का खजाना है पालक

हरी सब्जियों में पालक का नाम सबसे ऊपर है. यह शरीर के लिए काफी फायदेमंद है. इसमें शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन ए, फोलिक एसिड, प्रोटीन और लौह तत्व भरपूर मात्र में होते हैं. इसके सेवन कई रोगों से भी छुटकारा मिलता है.

यह हरी पत्तेदार सब्जी गुणों से भरपूर है. पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए इसका नियमित सेवन बेहतर माना जाता है. पालक में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्र में होते हैं. इसके अलावा विटामिन बी कॉम्पलैक्स, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम की भी प्रचुरता होती है. शोध के अनुसार एक कप पालक से दिन भर की मैग्नीशियम की जरूरत का 40 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है. मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए भी पालक अच्छा विकल्प है. दही के साथ कच्चे पालक का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और गुणकारी होता है.

इन रोगों से बचाता है -

ऑस्टियोपोरोसिस - खनिज तत्वों की प्रचुरता के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस को दूर रखता है.

आंखों की रोशनी - पालक मैकुलर डिजेनरेशन का जोखिम भी कम करता है. मैकुलर डिजेनरेशन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अंधेपन का मुख्य कारण है. इसके अलावा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और आंखों की रोशनी में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं.

शरीर की क्षतिपूर्ति में सहायक - प्रचुर मात्र में मौजूद फोलेट डीएनए और कोशिकाओं की सामान्य क्षति को पूरा करता है और इससे शरीर स्वयं अपने नुकसान की भरपाई कर लेता है.

एंटीऑक्सीडेंट - यह शरीर में उपापचय व अन्य सामान्य क्रियाओं के दौरान बननेवाले फ्री-रेडिकल्स से लड़ने में सहायक है. फ्री रेडिकल्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर तथा हृदयरोगों के कारण बन सकते हैं.

वजन घटाने में सहायक - इसमें फाइबर प्रचुर मात्र में होता है, इसलिए यह मोटापा घटाने के इच्छुक लोगों के लिए आदर्श आहार है. सलाद, सब्जी और जूस में पालक का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग बेहतर होता है.

पोस्टमेनोपॉजल सिंड्रोम - पालक में मौजूद मैग्नीशियम पीएमएस के लक्षणों में कमी लाता है. इस अवस्था में पेट फूलने जैसी शिकायतों से बचने के लिए पालक बेहतर विकल्प है.

प्रतिरक्षा प्रणाली बनाता है मजबूत - पालक में मौजूद पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और शरीर को सामान्य संक्रमणों से बचाते हैं.

बालों को मिले मजबूती - इसमें बालों के लिए आवश्यक विटामिन भी विशेष मात्र में होते हैं. बाल झड़ने से परेशान लोगों को कच्चे पालक का सेवन करना चाहिए.

ये लोग न करें सेवन - पालक में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, जो मिल कर कैल्सियम फॉस्फेट बनाता है. यह पानी में घुलता नहीं है, जिससे पथरी बन जाती है. इसलिए पथरी के रोगियों को सिर्फ पालक की सब्जी नहीं खानी चाहिए. पालक और हरी पतेवाली मेथी मिला कर साग बना कर खाने से पथरी नहीं बनती है. कच्चे पालक के रस के सेवन करने से भी पथरी नहीं होती है.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मोदी को मिला गुयाना-डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

जॉर्जटाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुयाना की यात्रा पर है। गुयाना में पीएम मोदी का भव्यता से स्वागत और सम्मान किया गया। गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति इरफान अली को गुयाना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं... यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का भी है। यह हमारे संबंधों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीता जागता सबूत है जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भारत और गुयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित हैं।

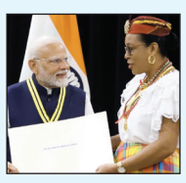

महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए 160 से 165 सीटें जीतेगी : राउत

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन कुल 288 में से 160 से 165 सीटें जीतेगा और राज्य में एक स्थिर सरकार प्रदान करेगा। राज्यसभा सदस्य राउत ने यह भी कहा कि एमवीए नेता शनिवार को होने वाली मतगणना से पहले बृहस्पतिवार को बैठक करेंगे। बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का अनुमाान जताया, जबकि कुछ ने पश्चिमी राज्य में एमवीए गठबंधन को बढ़त दी। राउत ने संवाददाताओं से कहा, ''हम और हमारे सहयोगी, जिनमें पीडब्ल्यूपी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल जैसे छोटे दल शामिल हैं, बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं। हम 160-165 सीटें जीत रहे हैं। राज्य में एक स्थिर सरकार होगी। मैं यह बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं।''

एनडीए के अलावा कोई और नहीं दे सकता स्थिर सरकार

भुवनेश्वर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। ओडिशा के उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कहा कि दो दिनों का और इंतजार है। मैं खुद महाराष्ट्र गया था चुनावी प्रचार के लिए जहां मैंने जमीनी स्तर पर देखा था कि लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं। भारत के लोग भी आज एक स्थिर सरकार चाहते हैं। एनडीए के अलावा, मुझे नहीं लगता कि आज देश में कोई और स्थिर सरकार दे सकता है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ, वहीं झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था।

बिटकॉइन घोटाले के आरोपों पर नाना पटोले ने तोड़ी चुप्पी

मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है। हालांकि, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले प्रशासन और उसके गठबंधन के खिलाफ जनता का गुस्सा स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोग भाजपा और उसके गठबंधन से नाराज हैं। यह गुस्सा उनके वोटों में दिखाई दे रहा है। वोट प्रतिशत बढ़ा है। बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने के आरोपों को संबोधित करते हुए, पटोले ने टिप्पणी की कि भाजपा की कार्रवाई न केवल डराने में विफल रही है, बल्कि उनकी पार्टी के लिए सहानुभूति भी पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस कदम पर लोग हंस रहे हैं। हमें जनता की सहानुभूति मिली है। महाराष्ट्र के लोग मेरे चरित्र को जानते हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी द्वारा शेयर किए गए ऑडियो को लेकर लोगों का मानना है कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है।

आम आदमी पार्टी की पहली सूची में 11 उम्मीदवारों का नाम

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पीएसी की बैठक बुलाई। पार्टी गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च फैसले लेने वाली संस्था पीएसी की बैठक गुरुवार को हुई। पीएसी की बैठक में दिल्ली विधानसभा 2025 चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक में आप के दिग्गज नेताओं ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। जिनमें छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, विश्वास नगर से दीपक सिंघला, रोहतास नगर से सरिता सिंह, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी, बदरपुर से राम सिंह, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धींगान, घोंडा से गौरव शर्मा, करावल नगर से मनोज त्यागी, मटियाला से सोमेश शौकीन आप के उम्मीदवार होंगे।

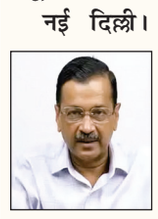

गौतम अडानी मामले को लेकर गर्म हुई सियासत

भाजपा ने कांग्रेस को दिखाया आईना रिपोर्ट की टाइमिंग पर खड़े किए सवाल

नईदिल्ली। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी पर कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाए जाने के बाद, भाजपा नेता अमित मालवीय ने गुरुवार को कहा कि संसद सत्र और डोनाल्ड ट्रम्प के आसन्न राष्ट्रपति पद से ठीक पहले रिपोर्ट का समय कई सवाल उठाता है। जयराम रमेश द्वारा मामले की जेपीसी जांच की मांग के बाद मालवीय ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। जयराम रमेश के दावों पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता ने लिखा कि किसी की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। आपके द्वारा उद्धृत दस्तावेज़ कहता है, अभियोग में आरोप आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे दोषी साबित न हो जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जैसा भी हो, आरोप का सार यह है कि अमेरिकी और भारतीय कंपनियां भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) को 12 गीगावॉट बिजली की आपूर्ति करने पर सहमत हुईं। यह एसईसीआई द्वारा राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ पीपीए में प्रवेश के अधीन था। अदानी ग्रीन एनर्जी के बीच अमेरिकी नवीकरणीय ऊर्जा, एज़्योर पावर के साथ एक सहयोग था, जिसके तहत एज़्योर को 4 गीगावॉट और अदानी ग्रीन एनर्जी को 8 मेगावाट आवंटित किया गया था। उन्होंने बताया कि कथित रिश्वत कांड में उन सभी राज्यों का जिक्र है जहां विपक्ष का शासन है।

अमित मालवीय ने लिखा कि यहां बताए गए सभी राज्य उस दौरान विपक्ष शासित थे। इसलिए, उपदेश देने से पहले, कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा ली गई रिश्वत पर जवाब दें। इसके अलावा, एक भारतीय अदालत इसी तरह, वैध आधार पर, अमेरिकी कंपनियों पर भारतीय बाजारों तक पहुंच से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा सकती है। तो क्या हमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए और संबंधित कॉरपोरेट को अपना बचाव करने देना चाहिए या किसी विदेशी देश की घरेलू राजनीति में खुद को स्थापित करने देना चाहिए? उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से उत्साहित न हों। संसद सत्र और डोनाल्ड ट्रम्प के आसन्न राष्ट्रपति पद से ठीक पहले रिपोर्ट का समय कई सवाल खड़े करता है। यह बात बहुत कुछ कहती है कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस और उनके गुट का सहारा बनने को तैयार है।

कांग्रेस ने उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरीकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि इससे उसकी यह मांग सही साबित होती है कि इस कारोबारी समूह से जुड़े पूरे प्रकरण की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन होना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि तत्काल जेपीसी का गठन होना चाहिए। अमेरिकी अभियोजकों ने अदाणी (62) और उनके भतीजे सागर अदाणी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सौर परियोजनाओं के अनुबंध और वित्त पोषण हासिल किए।

अडानी मामले में कांग्रेस ने की जेपीसी से जांच करवाने की मांग

नईदिल्ली। न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी और अन्य पर कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना में शामिल होने का आरोप लगाए जाने के बाद, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि इससे विभिन्न कथित घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की कांग्रेस की मांग सही साबित हुई है।

एक्स पर एक पोस्ट में, जयराम ने कहा, अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा गौतम अडानी और अन्य पर अभियोग लगाया जाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जनवरी 2023 से विभिन्न मोदानी घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की मांग को सही साबित करता है। कांग्रेस ने अपनी हम अडानी के हैं (एचएएचके) श्रृंखला में इन घोटालों के विभिन्न आयामों और पीएम और उनके पसंदीदा व्यवसायी के बीच मौजूद अंतरंग सांठगांठ को सामने लाते हुए सौ सवाल पूछे थे। ये सवाल अनुत्तरित रह गए हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी उल्लेख किया कि एसईसी की कार्रवाई उसके भारतीय समकक्ष, अर्थात् सेबी द्वारा अडानी समूह द्वारा प्रतिभूति और अन्य कानूनों के कथित उल्लंघन की जांच करने के तरीके पर भी गलत प्रकाश डालती है। जयराम रमेश ने आगे कहा, कांग्रेस अडानी समूह के लेन-देन की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की अपनी मांग दोहराती है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तथा विशेष रूप से हमारे पड़ोस में विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, गौतम अडानी, सागर आर. अडानी और विनीत एस. जैन पर प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी तथा प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए संघीय अदालत में पांच-अनुसूची आपराधिक अभियोग खोला गया, जिसमें झूठे और भ्रामक बयानों के आधार पर अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने की बहु-अरब डॉलर की योजना में उनकी भूमिका थी।

अभियोग में रंजीत गुप्ता और रूपेश अग्रवाल, एक अक्षय ऊर्जा कंपनी के पूर्व अधिकारी, जिनकी प्रतिभूतियों का कारोबार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (अमेरिकी जारीकर्ता) में हुआ था, तथा सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, जो एक कनाडाई संस्थागत निवेशक के पूर्व कर्मचारी थे, पर भी कथित रिश्वतखोरी योजना के संबंध में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप लगाया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने कहा, जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत योजना बनाई थी और गौतम एस. अडानी, सागर आर. अडानी और विनीत एस. जैन ने रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि वे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाना चाहते थे। अभियोग में कार्यपालक पर एफबीआई, न्याय विभाग (डीओजे) और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) की जांच में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है।

अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय का कहना है कि अभियोग में लगाए गए आरोप आरोप हैं और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। जांच एफबीआई न्यूयॉर्क की कॉर्पोरेट, सिक्योरिटीज और कमोडिटी धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार इकाइयों द्वारा की गई थी। सरकार का मामला न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के व्यापार और प्रतिभूति धोखाधड़ी अनुभाग तथा आपराधिक प्रभाग के धोखाधड़ी अनुभाग द्वारा संभाला जा रहा है। गौतम अडानी के कार्यालय या अभियोग में नामित अन्य लोगों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अगर प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अदाणी साथ हैं, तो सुरक्षित हैं : राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिश्वत मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उद्योगपति गौतम अदाणी की गिरफ्तारी की मांग की। अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा, जेपीसी की हमारी मांग कायम है। अदाणी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनकी ''संरक्षक'' माधबी पुरी बुच की जांच होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी और (गौतम) अदाणी साथ हैं, तो वे भारत में सुरक्षित हैं।

सौर ऊर्जा अनुबंध रिश्वत मामले में गौतम अदाणी और अन्य पर आरोप लगाने वाले अमेरिकी अभियोजकों को लेकर हंगामा जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह अब अमेरिका में बहुत स्पष्ट औरस्थापित है कि अदाणी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। उन्हें अमेरिका में दोषी ठहराया गया है।

मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अदाणी इस देश में एक आज़ाद आदमी के इर्द-गिर्द क्यों घूम रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदाणी ने जाहिर तौर पर 2000 करोड़ रुपये का एक घोटाला किया है और शायद कई अन्य घोटाले भी किए हैं, लेकिन वह बेदाग भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री अदाणी की रक्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अदाणी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल हैं।

अरबपति गौतम अदाणी के समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को 60 करोड़ डॉलर का बॉण्ड जारी करने से इनकार कर दिया। कंपनी के प्रवर्तक पर अमेरिका में कथित रिश्वतखोरी के एक मामले में आरोप लगाए गए हैं। उद्योगपति गौतम अदाणी पर अमेरिकी अभियोजकों के भारत में सौर बिजली अनुबंध हासिल करने के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाने से कुछ घंटे पहले कंपनी ने अमेरिकी निवेश-ग्रेड बाजार में 20 साल का हरित बॉण्ड बेचा था।

इस निर्गम को तीन गुना अभिदान मिला था लेकिन आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अदाणी ग्रीन एनर्जी ने शेयर एक्सचेंज को दी सूचना में बताया, '' अमेरिका के न्याय विभाग तथा प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने हमारे निदेशक मंडल के सदस्यों गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ क्रमशः न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में अमेरिकी जिला अदालत ने एक आपराधिक अभियोग जारी किया है और एक दीवानी शिकायत दर्ज की है।'' कंपनी की सूचना के अनुसार, '' अमेरिकी न्याय विभाग ने हमारे निदेशक मंडल के सदस्य विनीत जैन के खिलाफ भी इस तरह का आपराधिक अभियोग जारी किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी अनुषंगी कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित यूएसडी नामित बॉण्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है।''

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच आज से

पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत चुनौतीपूर्व टेस्ट सीरीज से पहले भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह ने गुरुवार 21 नवंबर 2024 को कहा कि उनकी टीम घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड से 0-3 से मिली हार का बोझ लेकर यहां नहीं आई है। हालांकि, उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि उनकी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से सबक जरूर लिया है। पांच मैच की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी शुक्रवार 22 नवंबर 2024 से शुरू होगी।

पिता बनने के कारण पहले टेस्ट से बाहर रोहित शर्मा की जगह कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने कहा कि, जब आप जीतते हैं तो शून्य से शुरुआत करते हैं, लेकिन जब हारते हैं, तब भी तो ऐसा ही होता है। हम भारत से कोई बोझ लेकर नहीं आए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज से हमने सबक लिया है। लेकिन यहां के हालात अलग हैं और यहां हमारे नतीजे अलग रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीम टॉस के समय ही अंतिम प्लेइंग इलेवन का खुलासा करेगी।

बुमराह ने आगे कहा कि, हमने आखिरी प्लेइंग इलेवन तय कर ली है और सुबह मैच से पहले आपको पता चल जाएगा। विराट कोहली से जुड़ा सवाल पूछने पर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि, मुझे कोहली को कोई इनपुट देने की जरूरत नहीं है मैंने उनके नेतृत्व में ही डेब्यू किया है। एक सीरीज में उतार-चढ़ाव हो सकता है लेकिन वह आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। वहीं बुमराह ने पर्थ टेस्ट में कप्तानी को लेकर कहा कि, जब मैं यहां आया था तभी कोच और प्रबंधन ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं टीम की अगुवाई करूंगा। जसप्रीत बुमराह को हमेशा से जिम्मेदारी और कठिन काम करना काफी पंसद रहा है। यही कारण है कि वह अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारत की अगुवाई करने का लुत्फ उठा रहे हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 422 अंक टूटा, निफ्टी 23,400 से नीचे आया

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 168 अंक फिसलकर 23,400 के लेवल से नीचे आ गया। अमेरिका में एक अदालत ने गौतम अदाणी को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया है। इस खबर के बाद ग्रुप के स्टॉक्स में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखी जा रही है। 30 शेयरों वाल, बीएसई सेंसेक्स 422.59 अंक या 0.54 प्रतिशत की गिरावट लेकर 77,155.79 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 76,802.73 और 77,711.11 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 168.60 अंक या 0.72 प्रतिशत की गिरावट लेकर 23,349.90 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 23,263.15 और 23,507.30 के रेंज में कारोबार हुआ।

अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 600 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना को वापस लिया

नईदिल्ली। अदाणी ग्रीन एनर्जी ने गुरुवार (21 नवंबर) को अमेरिकी डॉलर बांड के जरिए 600 मिलियन डॉलर जुटाने की अपनी योजना को वापस ले लिया। अमेरिकी अभियोजकों की तरफ से गौतम अदाणी और बोर्ड के अन्य सदस्यों पर 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत स्किम में शामिल होने के आरोपो के बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। इस संबंध में अमेरिकी सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज कमीशन और अमेरिकी जस्टिस विभाग (डीओजे) दोनों ने न्यूयॉर्क के अमेरिकी जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। एसईसी ने अदाणी ग्रुप के बोर्ड के सदस्यों गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ एक नागरिक कार्रवाई दायर की है। जबकि जस्टिस विभाग ने आपराधिक अभियोग जारी किया है।

एक साल में ये पांच शेयर करा सकते हैं अच्छा मुनाफा

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार (21 नवंबर) को तेज गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी बिकवाली का असर बाजार के मूड-माहौल पर देखने को मिली। इसके अलावा ग्लोबल सेंटीमेंट्स का असर घरेलू बाजारों पर पड़ रहा है। बाजार में जारी उठापटक के बीच लंबी अवधि के नजरिए से चुनिंदा शेयरों में खरीदारी का मौका भी है। ब्रोकरेज फर्म शेयरखान ने गुरुवार को अपने फंडामेंटल अपडेट में 5 स्टॉक्स में लंबी अव?धि के लिए निवेश की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीने के नजरिए से UPL, HDFC Life, Bharti Airtel, Affle India, Ashok Leyland स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दी है। इनमें निवेशकों को 29 फीसदी तक का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है।

जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस आईपीओ की लिस्टिंग टली

नईदिल्ली। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस शुक्रवार का आईपीओ शेयर बाजार में 21 नवंबर को लिस्ट नहीं होगा। कंपनी ने अपने आईपीओ की लिस्टिंग डेट बदल कर 22 नवंबर (शुक्रवार) कर दी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास दायर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, पहले कंपनी के शेयर 21 नवंबर को लिस्ट होने वाले थे। हालांकि, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने के कारण स्टॉक एक्सचेंज बंद रहे। इसकी वजह से लिस्टिंग को एक दिन के लिए टाल दिया गया। टी+3 लिस्टिंग नियम के अनुसार इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू को आईपीओ बंद होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाना आवश्यक होता है। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन आईपीओ को कुल मिलाकर 1.87 गुना सब्सक्राइब किया गया।

कितना कारगर रहा खरीद सुधारों का कदम?

विनायक चटर्जी

इस सदी के पहले 15 वर्षों में सरकार के साथ काम करने में भारतीय उद्योग जगत ने दो प्रमुख मुद्दों का मुखर होकर विरोध किया। एक भुगतान में अत्यधिक देर और चयन की एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) पद्धति में मौजूद खामियां।

ऐसा माना जाता है कि कई व्यवसाय ऐसे हैं जो कभी सरकार के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे, लेकिन तमाम कमियों के कारण उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जूझना पड़ा। अंततः वे धीरे-धीरे रास्ते से हट गए और देश गुणवत्तापूर्ण आपूर्तिकर्ताओं से वंचित हो गया।

ऐसा नहीं है कि सरकार इन मुद्दों के प्रति असंवेदनशील रही या इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए प्राप्ति पोर्टल (पेमेंट रेटिफिकेशन ऐंड एनालिसिस इन पॉवर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवाइसिंग ऑफ सप्लायर्स) ने बिजली वितरण कंपनियों द्वारा ऊर्जा उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान की प्रक्रिया में कमियों का पता लगाने और उनमें सुधार के लिए काफी काम किया। ऊर्जा मंत्रालय ने इसमें देरी करने वालों पर बहुत कड़ाई बरती।

सरकार ने समय-समय पर छोटी और मझोली कंपनियों का पैसा रोकने या देर से देने वालों पर जुर्माना लगाने तथा इस संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी कर सुधार के प्रयास किए। लेकिन, टीवी सोमनाथन (वर्तमान में कैबिनेट सचिव) जब वित्त मंत्रालय में थे, तो उन्होंने जमीन पर व्यवस्थित रूप से कार्रवाई करते हुए इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश की। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 29 अक्टूबर, 2021 को 'खरीद और परियोजना प्रबंधन पर सामान्य दिशानिर्देश' शीर्षक से एक

अधिसूचना जारी की थी। सुधारों पर अन्य सरकारी घोषणाओं के विपरीत इसे बहुत कम करके आंका गया, लेकिन यह जमीनी स्तर पर चुपचाप किए जाने वाले सुधारों का उत्कृष्ट उदाहरण था।

सामान्य तौर पर सरकारी सेवाओं और अनुबंधों के लिए खरीद में अव्यवस्था पर अपेक्षित कार्रवाई के लिए यह 22 पृष्ठों का नोटिस भर था, लेकिन इसकी जिस बात ने निजी क्षेत्र को राहत और खुशी दी, वह यह कि इसमें भुगतान में देरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायतें दी गई थीं। इसमें साफ तौर पर व्यवस्था की गई थी कि पात्र चालू खाता बिलों का कम से कम 75 प्रतिशत भुगतान बिल जमा करने के 10 कार्यदिवसों के भीतर किया जाना चाहिए। शेष पैसा बिलों की अंतिम जांच परख के बाद 28 कार्यदिवसों में हर हाल में दे दिया जाए।

इसके अलावा, परियोजनाओं पर काम करने वाली एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बिलों की निगरानी तथा ठेकेदारों को अपने बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया गया था। चयन के नियमों में भी सुधार किया गया।

सभी परामर्शदाता निविदाओं के लिए तीन खरीद प्रक्रियाओं- क्यूसीबीएस (क्वालिटी ऐंड कॉस्ट बेस्ड सेलेक्शन), एलसीएस (लीस्ट कॉस्ट सिस्टम) और एसएसएस (सिंगल सोर्स सेलेक्शन) का पालन पहले से किया जा रहा था। नए नियमों में एफबीएस (फिक्स्ड बजट सेलेक्शन) की व्यवस्था दी गई, जहां कीमत तय होती है और चयन अधिकतम योग्यता के आधार पर होता है। कार्य और गैर परामर्शदायी सेवाओं के लिए अधिसूचना में क्यूसीबीएस का रास्ता अपनाया गया, जिसकी सामान्य तौर पर अभी तक इजाजत नहीं थी। अब दो शर्तों के साथ इसे आगे बढ़ाया गया। एक, जहां परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्यूओपी (क्वालिटी-ओरिएंटेड प्रोक्योरमेंट) घोषित किया गया हो और दूसरा, गैर परामर्शी सेवाओं के लिए जहां अनुमानित खरीद मूल्य 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

क्यूसीबीएस के अंतर्गत गैर वित्तीय मानकों का अधिकतम भार 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बहुत अधिक आलोचनाओं में घिरी एल1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) व्यवस्था को अंततः समाप्त कर कर दिया गया।

वित्त मंत्री ने सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ

विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है सुशासनः चौधरी

रायपुर। सुशासन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे न केवल देश का सुव्यवस्थित विकास होता है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, जीएसटी, जैम पोर्टल, डिजिटल इनक्लुजन जैसे नवाचारों ने देश में बड़ा बदलाव लाया है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने नवा रायपुर में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा सुशासन पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए ये विचार व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर से आए भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधिकारी सम्मेलन में सुशासन के लिए किए जा रहे नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और जनोन्मुखी कार्यों पर विमर्श कर रहे हैं।

नागरिक केंद्रित सुशासन पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में ब्यूरोक्रेट्स की महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सम्मेलन में भागीदारी कर रहे विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से कहा कि सुशासन, नवाचार और बदलाव के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, ताकि आप लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व में क्षरण न हो। समय के साथ स्वयं को बदलने वाले ही प्रासंगिक

रहेंगे। चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सुशासन से वर्ष 2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी।

वित्त मंत्री चौधरी ने सम्मेलन में कहा कि कई कलेक्टर और अधिकारी प्रभावी नवाचार कर रहे हैं। समय और अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप बेहतर नागरिक सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, तभी कल्याणकारी पहलों को नागरिकों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिया तेजी से बदलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में दो दिनों तक होने वाले नवाचारों, बेस्ट प्रेक्टिसेस और सुशासन के कार्यों की चर्चा से राज्य के अधिकारी भी प्रेरित होंगे और उन्हें यहां लागू करने की पहल करेंगे। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की सफलता तभी है जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला पाएं। आपके लाभार्थी आपके कार्यों से संतुष्ट हैं, तो वही सुशासन की सफलता है। सुशासन के लिए लक्षित लोगों तक योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए अच्छी नीयत सबसे ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के गठन, रायपुर में कैनाल लिंकिंग रोड, एक्सप्रेस वे के निर्माण जैसे कई उदाहरण देते हुए कहा कि शासन-प्रशासन में यहां भी कई नवाचार हो रहे हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए उनके अनुरूप लोगों के कल्याण के काम हो रहे हैं। केन्द्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने उद्घाटन सत्र में कार्मिक एवं जन शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी।

भारत मंडपम में दूर से खड़े खड़े कार्यक्रम देख रहे थे एक बुजुर्ग, मुख्यमंत्री ने पास बुलाया और अपने साथ बैठने का किया आग्रह

नई दिल्ली/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सादगी और संवेदनशीलता ने एक बार फिर लोगों के दिलों को छू लिया। यह दृश्य था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। छत्तीसगढ़ की परंपरा और कला की शानदार प्रस्तुतियां मंच पर हो रही थीं, और दर्शक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री साय की नजर दर्शकों के बीच एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो खड़े होकर कार्यक्रम देख रहे थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत अपने सहायक से कहा कि उस बुजुर्ग को पास बुलाएं। कुछ ही पल में वह बुजुर्ग व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। श्री साय ने बड़े ही आत्मीय भाव से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने का आग्रह किया। कार्यक्रम देखकर बाहर आये बुजुर्ग श्री रामावतार तिवारी ने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुख्यमंत्री ने मुझे सम्मान दिया,

अपने पास बैठाया और मेरा हालचाल पूछा। मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ओहदा हासिल करने के बाद भी अपनी विनम्रता और संस्कार को नहीं छोड़ा। श्री रामावतार तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सीधे सरल लोगों के बारे में सुनते आये हैं। वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर लगा कि सीधे और सरल लोगों के मुखिया भी सीधे और सरल स्वभाव के हैं। मुख्यमंत्री श्री साय का हृदय संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। हम एक दूसरे से अपरिचित भले ही हो सकते हों लेकिन संवेदनशील हृदय के द्वारा हम एक दूसरे की भावनाओं को प्रगाढ़ता से महसूस कर सकते हैं।

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में 23 को मतगणना सुबह 8 बजे से होगी प्रारंभ

रायपुर। रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन के लिए मतगणना 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्मेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र 51-रायपुर नगर दक्षिण के उपनिर्वाचन की मतगणना तिथि 23 नवंबर दिन शनिवार को नियत है। मतगणना तिथि को मतगणना कार्य गवर्मेंट इंजीनीयरिंग कॉलेज, सेजबहार, रायपुर (ब्लॉक-ई) में सम्पन्न किया जाएगा। निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य मतगणना तिथि के दिन प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा, जिसमें प्रातः 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की

रायपुर नगर दक्षिण उपनिर्वाचन

गणना प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रातः 8.30 बजे से ईव्हीएम मशीनों के मतों की गणना प्रारम्भ होगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतगणना हॉल में ईव्हीएम में पड़े मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। यह गणना कुल 19 राउण्ड में पूरी होगी। पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 1 अतिरिक्त टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल के प्रत्येक टेबल में एक-एक काउटिंग सुपरवाईजर, काउटिंग असिस्टेंट एवं माइक्रो आब्जर्वर होंगे, जो मतगणना का कार्य संपादित करेंगे। मतगणना हॉल में ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की जानकारी को संधारित करने के लिए डाटा कम्पाइलेशन एवं अपलोडिंग सेक्शन बनाया गया है। मतगणना हॉल में अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के मतगणना एजेन्ट्स भी उपस्थित रह सकेंगे.

सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी

गुड गवर्नेंस की रीजनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट प्रेक्टिसेस पर हुई चर्चा

रायपुर में चल रही है 'गुड गवर्नेंस' पर दो दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस

रायपुर। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में ''गुड गवर्नेंस'' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार-विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यो से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं।

देश के विभिन्न राज्यों के 150 प्रतिनिधि ले रहे भाग

सम्मेलन के पहले दिन के दूसरे सत्र में ''जिला प्रशासन में महिला नेतृत्व'' विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने की। इस सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी एवं लखीमपुरी-खीरी की कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने सत्र को सम्बोधित किया। कलेक्टर श्रीमती मोनिका रानी ने सेवा से संतृप्तिकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें फील्ड में जाकर जनता से मिलकर शासकीय सेवाओं की सहजता से आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्टर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वे मल्टीटास्कर, प्राकृतिक रूप से देखभाल करने वाली और संवेदनशील होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिलाओं के समूह केले की खेती और सह-उत्पाद निर्माण और ई-कॉमर्स से अपने उत्पाद का विक्रय कर रहा है। महिला समूहों के इस कार्य की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की है।

धमतरी कलेक्टर श्रीमती नम्रता गांधी ने अपने व्यक्तव्य में नारी शक्ति से जल शक्ति जल जगार कार्यक्रम की सफलता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन विश्वास एवं जनसहयोग से बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जल जगार के बड़े सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जिले में जल संग्रहण और भू-जल स्तर बढ़ा है। फसल चक्र परिवर्तन किसानों ने अपनाया है। उन्होंने बच्चों के मेंटल हेल्थ, एजुकेशन विशेषकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

सम्मेलन के तीसरे सत्र ''जिलों का समग्र विकास'' विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक ने की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.